आज का विचार
रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है... इस प्यार और विश्वास से ही मजबूत बनाया जा सकता है।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

3

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 वर्ष 24, अंक 84, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज होशियारपुर में बनाया जाएगा, जो दो वर्षों में पूरा होगा: मान

क्षेत्र में सात अन्य हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र विकसित किए जाएंगे, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार होगा: मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता
होशियारपुर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज होशियारपुर में 516 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विस्तार और जमीनी स्तर पर नई परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दो वर्षों के भीतर पूरा हो जाएगा, जहां वार्षिक 100 एमबीबीएस डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा ओपीडी, एमआरआई, सिटी स्कैन और विशेष विभागों सहित उन्नत सुविधाओं से लैस 300 बिस्तरों वाला अस्पताल भी बनाया जाएगा।

जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाम चौरासी में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी, जो आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, लैब, एक्स-रे, टीकाकरण और प्रसव देखभाल सेवाओं से सुसज्जित है, जिससे 40 से अधिक गांवों को लाभ होगा। उन्होंने हर कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्र में सात अतिरिक्त हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों की भी घोषणा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार लोगों के घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम स्तर तक मजबूत करते हुए उन्होंने क्षेत्र में सात और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के साथ-साथ 40 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचाने के लिए 9.18 करोड़ रुपये के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नींव पत्थर भी रखा। विकास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 99 करोड़ रुपये के बलाचौर-गढ़शंकर-होशियारपुर-दसूहा सड़क प्रोजेक्ट की शुरूआत की, जो 105 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। यह चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क बढ़ाएगा, जम्मू और दिल्ली के बीच यात्रा के समय को कम करेगा तथा आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी और माता ज्वाला जी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराएगा। शाम चौरासी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, आजादी के बाद 70 साल से अधिक समय तक पारंपरिक विरोधी पार्टियों ने राज्य को बेरहमी से लूटा है। इन पार्टियों की पिछड़ी और विभाजनकारी नीतियों के कारण राज्य विकास की रफ्तार से पिछड़ गया, जिससे लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि पिछले चार वर्षों में राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया गया है और पहली बार राज्य सरकार ने इतने कम समय में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य के विकास को सही दिशा में डाला गया है और अब पंजाब सरकार हर बीतते दिन के साथ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। राज्य सरकार ने 70 वर्षों का अंतर भर दिया है और अब रंगला पंजाब बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। आप सरकार देश की पहली सरकार है, जिसने लोगों के लिए चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया है, क्योंकि लोगों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों को अमल में लाया जा रहा है। बड़ी विकास पहलों को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, आज शाम चौरासी में 385 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली को बढ़ावा देंगे। उन्होंने आगे कहा, होशियारपुर में 268 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जो आम लोगों के लिए बड़ा तोहफा होगा। यह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाने में भी मदद करेगा।

शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को इसी माह से मिलेगा बढ़ा मानदेय: योगी

चार जिलों के 12 हजार से अधिक विस्थापित परिवारों को नागरिकता पात्रता के संबंध में प्रस्ताव पारित

एजेंसी (हि.स.)
लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में 10-10 हजार रुपये की मासिक बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे दी है। यह बढ़ा हुआ मानदेय इसी माह अप्रैल से दिया जाएगा।सरकार ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर व बिजनौर के 12 हजार से अधिक विभाजन समय से विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता के सम्बंध में प्रस्ताव सहित कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी अनुमोदित कर दिया है।

मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और वन मंत्री अरुण सक्सेना ने लोकभवन के मीडिया सेंटर में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी। मंत्री खन्ना ने बताया कि उप्र सरकार 25 लाख स्मार्ट टैबलेट खरीदेगी। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है। यह टैबलेट उप्र में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इनमें ज्यादातर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी होंगे। इससे पहले 60 लाख स्मार्ट फोन एवं टैबलेट खरीदे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास विभाग के आठ प्रस्ताव कैबिनेट में आए। सभी प्रस्तावों को अनुमोदन मिल गया है। सभी आठ प्रस्ताव निवेश से जुड़े हैं। इसमें बुंदेलखण्ड में 100 एकड़ में सोलर प्लांट स्थापित किए जाने, प्रयागराज में 231 करोड़ के निवेश से वाटर प्लांट स्थापित किए जाने, सोलर सेल निर्माण इकाई स्थापित करने संबंधी अन्य प्रस्तावों को मंजूरी शामिल है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर व बिजनौर में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए परिवारों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता के सम्बंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनकी संख्या लखीमपुर खीरी में 2350 परिवार, पीलीभीत में 4 हजार परिवार, बिजनौर में 18 ग्रामों में 3856 परिवार और रामपुर में 16 ग्रामों में 2174 परिवारो को लाभ मिलेगा।

पत्रकार वार्ता में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के सम्बंध में प्रस्ताव शामिल है। पहले फेज में पीपीपी मॉडल पर 23 बस अड्डों की एल.वाई जारी हो गई थी। आज 49 बस अड्डों की स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर 52 जनपदों को इससे आच्छादित किया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने बताया कि यह पीपीपी मॉडल के बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज पर होंगे। सुविधाओं को एयरपोर्ट की तर्ज पर दिया जाएगा। जनपद हाथरस में सिकन्दराराऊ कस्बे में कृषि विभाग के दो हेक्टेयर भूमि को बस अड्डा के लिए निःशुल्क प्राप्ति पर स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार जनपद बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग की जमीन बस अड्डे के लिए दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन मिला है। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में पीडब्ल्यूडी की भूमि को बस अड्डा निर्माण के लिए दिए जाने को स्वीकृति दी गयी।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सभी अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षामित्रों का मानदेय आठ-आठ हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया है। शिक्षामित्रों का मानदेय अब 18 हजार होगा। उन्होंने बताया कि उप्र में एक लाख 42 हजार 929 शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं। एक लाख 29 हजार 332 शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र का अंश बढ़ाया गया है। 30 हजार के आस-पास शिक्षा मित्रों का अतिरिक्त व्यय भार भी राज्य सरकार वहन करेगी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से ही लागू होगी। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का भी बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा। प्रदेश के 13 हजार 769 विद्यालयों में अधिकतम 24 हजार 716 अनुदेशक कार्यरत हैं। अनुदेशकों को पहले नौ हजार रुपये प्रति माह मिल रहा था। अब उन्हें 17 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा।

राजनाथ का ममता सरकार पर हमला बोले- बंगाल की स्थिति को किया बदतर

एजेंसी (हि.स.)
उत्तर 24 परगना

उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में पश्चिम बंगाल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने बैरकपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के तीन कार्यकाल के दौरान राज्य की आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था में बंगाल का हिस्सा लगभग 10 प्रतिशत से ज्यादा था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब बंगाल का देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सा घटकर लगभग 6 प्रतिशत रह गया है।

राजनाथ ने कहा कि जहां देश के अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में निवेश का माहौल कमजोर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई उद्योग राज्य से बाहर चले गए हैं और नए निवेशक भी यहां आने से हिचकिचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के राज में हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां न्याय देने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं। आज प्रदेश में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को रातभर बंधक बना लिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि बंकिमचंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम् के रूप में केवल शब्द ही नहीं दिए थे, बल्कि एक सोई हुई और अपनी पहचान खो चुकी सभ्यता को उसका आत्मबोध भी कराया था। बंकिम बाबू ने भारतवासियों को यह याद दिलाया कि हम सभी भारत माता की संतान हैं। उन्होंने लोगों को स्वधर्म का महत्व समझाया और यह बताया कि स्वराज और स्वधर्म की कीमत क्या होती है।

सिंह ने कहा कि भाजपा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि काजी मासूम अख्तर बच्चों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के लिए प्रेरित करते थे, जिसके कारण उस समय उन्हें तृणमूल सरकार द्वारा सजा दी गई थी, लेकिन उन्हीं काजी मासूम अख्तर को वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए केंद्र सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, न कि सांप्रदायिकता फैलाने में। राजनाथ सिंह ने भाजपा के विकास संबंधी एजेंडे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में बुनियादी ढांचे का विस्तार, उद्योगों की वृद्धि, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के निवेशक बंगाल की धरती पर निवेश करें, ताकि राज्य के लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके और बंगाल विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ सके। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

आधुनिक विकास को परंपराओं और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ना जरूरी: उपराष्ट्रपति

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 39वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिक विकास को नैतिक मूल्यों और भारतीय परंपराओं के साथ संतुलित करना आवश्यक है, ताकि समावेशी और जिम्मेदार समाज का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर 3.2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति ने डिजीलॉकर के माध्यम से प्रमाणपत्र जारी किए और इग्नू एलुमनाई पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसके नैतिक मूल्य हैं और विकास की दिशा में आगे बढ़ते समय परंपराओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिक उन्नति को नैतिकता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाना समय की मांग है।

उपराष्ट्रपति ने इग्नू की भूमिका की सराहना करते हुए इसे देश में समावेशी और सुलभ उच्च शिक्षा का मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाकर सामाजिक समानता और अवसरों का विस्तार किया है। उन्होंने बताया कि इग्नू में 14 लाख से अधिक शिक्षार्थी हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों की है।

मोदी के नेतृत्व में शांति लौटने के बाद विकास के पथ पर अग्रसर असम: शाह

एजेंसी (हि.स.)
हैलाकांदी

आसन्न असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतिम चरण के प्रचार के दौरान बराक घाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में असम में शांति वापस आई है और राज्य अब तेज गति से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को बराक घाटी के तीन जिलों श्रीभूमि, हैलाकांदी और सिलचर में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। श्रीभूमि जिला के पथारकांदी में भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल, हैलाकांदी में भाजपा उम्मीदवार डॉ. मिलन दास के समर्थन में सभा में शामिल हुए। उसके बाद वे सिलचर में डॉ. राजदीप रॉय और उदारबंद सीट से राजदीप गोवाला के पक्ष में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

जनसभाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और भाजपा सरकार के दौरान राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि असम को देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले पांच वर्षों में इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने भूमि पट्टा वितरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और श्रीभूमि में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है। साथ ही, आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं।

अमित शाह ने सिलचर के विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गुवाहाटी की दूरी को देखते हुए सिलचर को ही एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को अपने कार्यों के लिए गुवाहाटी जाने की आवश्यकता न पड़े। इसके अलावा किसानों के लिए भी विभिन्न सुविधाएं और योजनाएं लागू की जाएंगी।

केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य की ओर कर रही तेजी से कार्य: शिवराज सिंह

एजेंसी (हि.स.)
जयपुर

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारत की रीढ़ है तथा किसान इस देश की आत्मा हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन स्तर में सुधार करते हुए कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने राजस्थान में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि का रोडमैप तैयार किया गया है। चौहान ने अन्य राज्यों को भी इस नवाचार का अनुसरण करने का संदेश दिया।

चौहान मंगलवार को जयपुर में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में पहला क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ राजस्थान से किया गया है। उन्होंने खेती से जुड़े इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का राजस्थान में आयोजन होने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा तथा राजस्थान राज्य शामिल है तथा इस सम्मेलन में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का एक मंच मिलेगा। साथ ही, सम्मेलन से राज्यों के बीच आपसी समन्वय व नवाचारों को भी साझा कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति मिले। दूसरे लक्ष्य के तहत किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही, तीसरे लक्ष्य के रूप में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए उत्पादन वृद्धि, कृषि का विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली जैसी पहलों के माध्यम से पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

चौहान ने कहा कि सभी राज्य मिशन मोड पर कार्य करते हुए फार्मर आईडी के तहत 100 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण करवाए जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सके। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न जोखिमों से किसानों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन करें, जिससे किसानों को बीमा योजना का लाभ त्वरित मिल सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कृषि के संभावनाओं को देखते हुए कृषि के रोडमैप बनाने की पहल की गई है। अन्य राज्य भी इससे प्रेरणा लेकर कृषि का रोडमैप बनाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी समय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें भी केंद्र सरकार विशेषज्ञों, अधिकारी तथा वैज्ञानिकों की टीम भेजेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि किसान देश की नींव हैं और देश का विकास गांव की पगडंडियों, खेत-खलियानों से होगा। उन्होंने संवेदनशीलता के साथ किसान हित में निर्णय लेते हुए पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाया। प्रदेश में हमारी सरकार ने इसमें 3 हजार रुपये और जोड़कर इसे 9 हजार रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मई माह में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश-विदेश के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों को जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार किसान हितों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना तैयार की है जिसके तहत फसल श्रेणी वार लक्ष्यों का निर्धारण किया है। हमने कृषि बजट में 34 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अब पारंपरिक तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कृषि नौकरी और व्यापार से भी अधिक लाभकारी बन सके।

मुख्यमंत्री ने किसानों से कृषि में आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और पारंपरिक फसलों के साथ आधुनिक फसलों को शामिल करने का आान किया। साथ ही, उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता जताते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खाद प्रयोग करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भूमि की उर्वरता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कृषि के साथ पशुपालन को जोड़ने पर विशेष बल दिया ताकि प्राकृतिक खाद की उपलब्धता बढ़े और लागत में कमी लाकर किसानों की आय को बढ़ाया जा सके।

सुक्खू सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर लगाई रोक

कहा, अब से किसी भी विभाग की ओर से सेवा विस्तार, कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा जाएगा

सरकार का अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

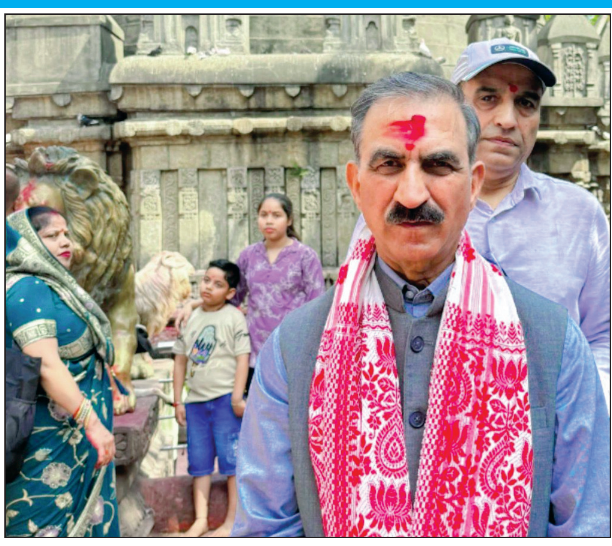

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदेश में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या दोबारा अनुबंध पर रखने के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले को वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि अब से किसी भी विभाग की ओर से किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या पुनः नियुक्त करने से जुड़ा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा जाएगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि यदि ऐसे प्रस्ताव भेजे भी जाते हैं, तो उन्हें किसी भी स्तर पर विचार के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है और इसे अत्यंत जरूरी श्रेणी में रखा गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इन निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी पहले से सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति या पुनः नियुक्ति पर कार्यरत हैं, वे अपनी तय अवधि पूरी होने तक ही सेवा में रहेंगे। उनकी अवधि समाप्त होते ही उन्हें स्वतः सेवानिवृत्त माना जाएगा और आगे कोई अतिरिक्त विस्तार नहीं दिया जाएगा।

सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में कई कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खु द्वारा पेश किए गए राज्य के बजट में भी खर्चों पर नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं। बजट में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का 50 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक हिस्सा अगले छह महीनों के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया था। इसे सरकार की वित्तीय अनुशासन की दिशा में एक बड़ी पहल माना गया था। दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से आरडीजी (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) समाप्त किए जाने के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है। सरकार का कहना है कि इसी वजह से संसाधनों के बेहतर उपयोग और खर्चों में संतुलन बनाए रखने के लिए कई कठिन लेकिन जरूरी फैसले लेने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आने वाले समय में भी सरकार वित्तीय सुधार के लिए और कड़े कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खु पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से कई फैसले ले रही है। उनका कहना है कि कठिन फैसले अल्पकाल में चुनौतीपूर्ण जरूर होते हैं, लेकिन लंबे समय में प्रदेश के हित में साबित होंगे।

जनता पर टैक्स का बोझ, सरकार मौज में कांग्रेस राज में हिमाचल त्रस्त : डॉ. राजीव बिंदल

कहा, प्रदेश में एक के बाद एक टैक्स लगाकर आम जनता की कमर तोड़ दी गई

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक का आयोजन मंडी में किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता आज महंगाई, टैक्स और कुशासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जनता की सेवा के बजाय जनता पर बोझ डालने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक टैक्स लगाकर आम जनता की कमर तोड़ दी गई है। बिजली के बढ़े हुए बिल करंट मारने लगे हैं, पानी के दामों में वृद्धि हुई है, एचआरटीसी के किराए बढ़ाए गए हैं और कई रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे आम लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। डॉ. बिंदल ने कहा कि राशन डिपो में लोगों को पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है वह महंगे दामों पर दिया जा रहा है। स्टांप ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी, सीमेंट के बढ़ते दाम और एंट्री टैक्स ने आम जनता, व्यापारियों और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने डीजल पर पहले 10.40 रूपए का वैट लगाया और अब 5 रूपए प्रति लीटर सेस लगाकर महंगाई को और बढ़ा दिया है, जबकि केंद्र सरकार लगातार राहत देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहत, दूसरी तरफ लूट, यही कांग्रेस सरकार का असली चेहरा है। डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज, भाई-भतीजावाद और मित्रवाद चरम पर है, जबकि बेरोजगार युवा, महिलाएं, कर्मचारी, किसान, बागवान और सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी वर्ग अपने-अपने स्तर पर परेशान हैं। आज हर वर्ग परेशान है और हर घर में आक्रोश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा प्रदेश कार्यसमिति में यह संकल्प लिया गया है कि जनता के हर मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाया जाएगा और हर वर्ग की आवाज बनकर संघर्ष किया जाएगा। डॉ. बिंदल ने कहा, यह लड़ाई भाजपा की नहीं, बल्कि जनता की है और भाजपा जनता के साथ मिलकर इस जनविरोधी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग उपस्थित रहे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, डॉ. राजीव भारद्वाज, हर्ष महाजन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, महामंत्री संजीव कटवाल, पायल वैद्य सहित सभी विधायक एवं प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे।

व्यवस्था परिवर्तन नहीं, कर और कर्ज.बढ़ाने का मॉडल बनी सुक्खू सरकारः जयराम

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को मंडी में कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो मॉडल प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में करों का बोझ बढ़ाने, कर्ज.बढ़ाने, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने का मॉडल बनकर रह गया है। जनता से किए गए वादों को निभाने के बजाय सरकार झूठी गारंटियों का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करती रही है।

उन्होंने कहा सहारा योजना जैसी महत्वपूर्ण पेंशन को बंद करने के लिए गरीब और असहाय लोगों को कागजों में ही मृत दिखाने जैसी अमानवीय कोशिशें की जा रही हैं। हिमकेयर जैसी जनकल्याणकारी योजना को बदनाम कर बंद करने की साजिश रची जा रही है, जिससे प्रदेश की गरीब जनता का स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र कमजोर हुआ है। आज लोगों के इलाज से भटकने, इलाज दवाई न मिलने की खबरें आम हो गई हैं। इस सरकार ने एक इंजेक्शन के लिए बेटी के सर से पिता का साया छीन लिया। मंगलसूत्र बिकवा दिया, मां के जेवर गिरवी रखवा दिए। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री की सिस्टम से पकड़ कमजोर होती जा रही है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों के सामने वह नतमस्तक हैं। कंप्रोमाइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सरकार इसपर आंख, कान और नाक बंद कर रखे हैं। बड़े घोटालों में कार्रवाई के बजाय लीपापोती की जा रही है। जब सरकार खुद अपने बयानों में उलझती दिखे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है।

कटड़ा व श्री माता वैष्णो देवी भवन की सुरक्षा व्यवस्था का डीआईजी ने किया व्यापक निरीक्षण

कटड़ा। उधमपुर-रियासी रेंज के डीआईजी पद का कार्यभार संभालने के बाद डीआईजी ने मंगलवार को कटड़ा नगर और श्री माता वैष्णो देवी भवन की सुरक्षा व्यवस्था का जमीनी स्तर पर विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से भवन तक जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने ट्रैक पर स्थापित सीआरपीएफ कैंप, संयुक्त चेक प्वाइंट और सुरक्षा पिकेट्स का दौरा किया। रणनीतिक और संवेदनशील स्थानों पर तैनाती का गहन आकलन करते हुए एक्सेस कंट्रोल, निगरानी व्यवस्था और क्षेत्र प्रभुत्व (एरिया डोमिनेशन) पर विशेष ध्यान दिया गया। डीआईजी ने थाना कटड़ा, थाना भवन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कटड़ा और जेसीआर भवन का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर आईसीसीसी की कार्यप्रणाली, सीसीटीएनएस सिस्टम की स्थिति और एसओजी कटड़ा की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा डीआईजी ने सीआरपीएफ, फायर ब्रिगेड, मेडिकल, आपदा प्रबंधन विभाग और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी समन्वय और सुरक्षा रणनीति पर चर्चा की।

बहुतकनीकी कॉलेजों में 60 शिक्षकों की भर्ती होगीः मंत्री राजेश धमार्णी

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार बदलती जरूरतों के अनुसार बहुतकनीकी कॉलेजों और अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में बहुतकनीकी कॉलेजों में शिक्षकों के 60 पद भरे जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

मंगलवार को बड़ू में बहुतकनीकी महाविद्यालयों की 27वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि खेलकूद, एनसीसी, सांस्कृतिक गतिविधियां और अन्य सह-पाठयक्रम कार्यक्रम शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके बिना शिक्षा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि ये गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं और उनके व्यक्तित्व को नई दिशा देती हैं। उन्होंने कहा कि बहुतकनीकी कॉलेजों में इन गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राजेश धर्माणी ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। विद्यार्थियों को बेहतर अवसर देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की नवरत्न कंपनियों और कॉरपोरेट क्षेत्र की अन्य बड़ी कंपनियों में अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने इनोवेशन पॉलिसी शुरू की है, जिसके तहत दो करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। इस योजना में नए विचारों के साथ काम करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसके अलावा प्लेसमेंट और मेंटोरशिप के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा।

संक्षिप्त-समाचार

हमीरपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा 79वां हिमाचल दिवस

हमीरपुर। 79वां हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को जिला हमीरपुर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां आरंभ कर दी हैं। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने मंगलवार को हमीर भवन में जिला के अधिकारियों के साथ बैठक करके जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों की समीक्षा की।उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल सीनियर सेकंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह का शुभारंभ सुबह 11 बजे ध्वजारोहण के साथ होगा। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, पुलिस, होमगार्ड्स और अन्य विभागों के अधिकारियों को आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर मंच निर्माण, ग्राउंड की मार्किंग, पेयजल एवं सफाई व्यवस्था, बिजली की आपूर्ति, बैठने की व्यवस्था, प्रतिभागियों के लिए जलपान और अन्य प्रबंधों में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। मौसम के खराब रहने की स्थिति के लिए भी अतिरिक्त प्रबंध होने चाहिए।उन्होंने बताया कि समारोह में आयोजित होने वाली भव्य परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड्स के अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स तथा अन्य टुकड़ियां भी भाग लेंगी। संबंधित पुलिस अधिकारी परेड की रिहर्सल जल्द शुरू करवाएं और इसमें अधिक से अधिक टुकड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। समारोह में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल के लिए भी उपायुक्त ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए तथा कहा कि ये कार्यक्रम उच्च स्तर के होने चाहिए। समारोह के अन्य प्रबंधों को लेकर भी उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

चिट्टा तस्करी में सप्लायर सहित दो गिरफ्तार

शिमला। राजधानी शिमला में चिट्टा तस्करी के एक मामले में पुलिस ने सप्लायर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में पहले शिमला के अनाडेल निवासी एक युवक को 36 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ पकड़ा गया, जबकि बाद में जांच के दौरान उसके सप्लायर को भी हमीरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से नशा तस्करी के नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी का खुलासा हुआ है और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।पुलिस थाना बालूगंज में इस संबंध में 6 अप्रैल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल शिमला की टीम उस समय नियमित गश्त और चेकिंग पर थी। इसी दौरान अनाडेल चौक के पास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर चिट्टा लेकर आ रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठाकुर बाग के पास नाका लगाया और संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोक लिया। बाइक सवार की पहचान गगन दीप सिंह उर्फ दीपू (33 वर्ष), निवासी गुरु नानक कॉटेज, अनाडेल, शिमला के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मोटरसाइकिल की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के साइड पैनल में छिपाकर रखा गया करीब 36 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

लश्कर के आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, 16 साल से फरार सरगना समेत पांच गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला 16 साल से फरार था और उसने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर ठिकाना बना रखा था। जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों के इस ऑपरेशन में एक अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान उर्फ बैब को भी गिरफ्तार किया गया है। जांचकताओं ने जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा समेत 19 स्थानों पर तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। जांच में लश्कर-ए-तैयबा के एक गहरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो आतंकवादियों को रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करने में शामिल था। पकड़े गए पांच लोगों में मोहम्मद नकीब भट, आदिल राशिद भट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा श्रीनगर के निवासी हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह तीनों आतंकवादियों को आश्रय और भोजन सहित रसद सहायता प्रदान करते थे। अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चलता है कि एक विदेशी आतंकवादी ने अन्य राज्यों में लश्कर-ए-तैबा नेटवर्क की मदद से जाली दस्तावेज और पहचान के आधार पर देश से बाहर यात्रा की। ये आतंकवादी लगभग 16 साल पहले भारत में घुसपैठ कर चुके थे और इस दौरान कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में सक्रिय रहे।

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में बारिश बर्फबारी, तूफान का पूवार्नुमान जताया

श्रीनगर। आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश के मौसम का एक ताजा दौर प्रभावित होने वाला है। मौसम विभाग ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश, बर्फबारी और तूफान की संभावना जताई है। नवीनतम मौसम अपडेट के अनुसार 7 और 8 अप्रैल को अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है विशेष रूप से रात के दौरान, अलग-अलग स्थानों पर गरज, बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चल सकती हैं। 9 और 10 अप्रैल को भी मौसम अस्थिर रहने की उम्मीद है और कई स्थानों पर खासकर दोपहर के समय हल्की बारिश की संभावना है। उसके बाद स्थितियों में सुधार होने का अनुमान है।

अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा मजबूत करने की मांग

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले शिवखोड़ी मार्ग पर लगी पाबंदियों को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर इन पाबंदियों को नहीं हटाया गया तो शिवसेना स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर व्यापक जनआंदोलन करेगी। इस संबंध में पार्टी ने उपराज्यपाल को एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा है।

प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा नजदीक है और देशभर से लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुंचने वाले हैं। इनमें बड़ी संख्या शिवखोड़ी के दर्शन के लिए भी जाती है। ऐसे समय में मार्ग पर जारी पाबंदियां न केवल श्रद्धालुओं में असमंजस और भय पैदा कर रही हैं बल्कि पूरे देश में नकारात्मक संदेश भी दे रही हैं। उन्होंने बताया कि 9 जून 2024 को श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने कटरा-रयासी-रानसू मार्ग पर कन्वॉय सिस्टम और निर्धारित समय में ही आवाजाही जैसी सख्त पाबंदियां लागू की थीं। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इन प्रतिबंधों का जारी रहना समझ से परे है, उन्होंने कहा। साहनी ने आरोप लगाया कि इन पाबंदियों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है जिससे रानसू और आसपास के क्षेत्रों में हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय दुकानदारों, होटल मालिकों और टैक्सी चालकों के अनुसार सीजन के बावजूद बाजार सूने पड़े हैं और व्यापार ठप होने की कगार पर है। उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ पहलगाम समेत कश्मीर के पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है वहीं जम्मू के प्रमुख धार्मिक स्थल शिवखोड़ी पर अनावश्यक पाबंदियां जारी रखना साफ तौर पर भेदभाव को दशार्ता है। साहनी ने कहा कि अत्यधिक प्रतिबंध सुरक्षा का विश्वास बढ़ाने के बजाय भय का माहौल बनाते हैं। उन्होंने स्मार्ट सिक्योरिटी मॉडल लागू करने की वकालत करते हुए पूरे मार्ग पर अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन पेट्रोलिंग, लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने और क्विक रिस्पांस टीम (क्युआरटी) की प्रभावी तैनाती की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पाबंदियां नहीं हटाई गईं तो शिवसेना ह्लशिवखोड़ी अधिकार आंदोलनह्व शुरू करेगी और जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी।

उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू-कश्मीर में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया

श्रीनगर। उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू-कश्मीर में व्यापक पौधरोपण अभियान चलाया। यह अभियान जम्मू से शिक्षा, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू द्वारा औपचारिक रूप से शुरू किए गए 'ग्रीन जम्मू-कश्मीर मिशन' के अनुरूप है। इस विजन के अनुरूप महाविद्यालय निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर के कॉलेजों में वृक्षारोपण अभियान के कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की। इस योजना के तहत सक्रिय संस्थागत भागीदारी, उपयुक्त वृक्षारोपण स्थलों की पहचान, निगरानी तंत्र और दीर्घकालिक पारिस्थितिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए पौधों के सतत रखरखाव के साथ, जम्मू-कश्मीर के लगभग 145 कॉलेजों में लगभग 10,000 पौधे लगाने की योजना बनाई गई थी। श्रीनगर में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा ने अमर सिंह कॉलेज में पौधे लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत की। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शफकत इकबाल और महाविद्यालय निदेशक डॉ. शेख एजाज बशीर ने श्रीनगर के एम.ए. रोड स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज बेमिना और सरकारी डिग्री कॉलेज महिला विभाग में पौधे लगाए।

नूरपुर में 1.256 किलोग्राम चरस और एक लाख नकदी के साथ शिमला का तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

नशामुक्त हिमाचल अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना नूरपुर के तहत पड़ने वाली पुलिस चौकी कंडवाल की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा कार से भारी मात्रा में चरस और नकद राशि बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता बीती देर रात उस समय मिली जब पुलिस चौकी कंडवाल की टीम एनएच-154 (मंडी-पठानकोट मार्ग) पर यातायात चेकिंग के लिए तैनात थी। इसी दौरान जसूर की तरफ से आ रही एक काले रंग की क्रेटा कार (एचपी-25सी-6008) को जब रुकने का इशारा किया गया तो चालक ने पुलिस पार्टी को देखकर गाड़ी पीछे मोड़ने का प्रयास किया।

संदेह होने पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को घेरा और काबू किया। स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जब गाड़ी की गहनता से तलाशी ली गई, तो डिग्गी में रखे स्पेयर टायर के नीचे छुपाए गए एक बैग से 1 किलो 256 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके अतिरिक्त बैग की जेब से एक लाख रुपये भी बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान राम कुमार (उम्र 52 वर्ष), निवासी तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कुल्लू-मनाली क्षेत्र में एक ढाबा चलाता है। पुलिस ने चरस, नकद राशि और तस्करी में प्रयुक्त कार को कब्जे में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस-1.89 लाख बच्चों को दवा देने का लक्ष्य, डीसी ने की तैयारियों की समीक्षा

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। यह बैठक डीसी कार्यालय परिसर में आयोजित हुई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय रैना ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कवर करेगा। कृमि संक्रमण से बच्चों में एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याएं होती हैं, जिन्हें रोकने के लिए एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि 13 अप्रैल 2026 को एनडीडी मनाया जाएगा, जबकि 18 अप्रैल को एमओपी-यूपी डे रखा गया है। इस दौरान स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 1,89,689 बच्चों को दवा दी जाएगी। डीसी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीडीएस विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को स्वच्छता व पोषण के प्रति जागरूक करना जरूरी है। नोडल अधिकारी डॉ. रुपाली ने कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

स्वास्थ्य दिवस | **स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान आरोग्य शिविर का किया शुभारंभ**

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया टीबी-मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट डैहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित आयुष्मान आरोग्य शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत की परिकल्पना के अनुरूप सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य ने प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। कविंद्र गुप्ता ने क्षय रोग की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टीबी आज भी समाज में एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, हालांकि राज्य इस बीमारी से निपटने में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में टीबी के मामलों की संख्या वर्ष 2022 में 15,760 से घटकर वर्ष 2025 में 14,653 हो गई है, जो स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों और समाज की सामूहिक भागीदारी को दशार्ता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में ज्यादा जोखिम वाले लगभग 1.49 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से लगभग सात लाख 46 प्रतिशत लोगों की जांच एक्स-रे के माध्यम से की गई, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। उन्होंने कहा कि शिविरों में आधुनिक हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनों और उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए निःशुल्क जांच की जा रही है, जबकि मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां दूरदराज और कठिन क्षेत्रों तक सेवाएं सुनिश्चित कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि टीबी-मुक्त ग्राम पंचायत पहल के तहत सामुदायिक प्रयासों से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं।

राज्यपाल ने किया बीबीएमबी ड्रेजर कॉम्प्लेक्स का दौरा

मंडी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के ड्रेजर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल को प्रबंधन बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों और संचालन तंत्र के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होंने जल निकासी की तकनीकी व्यवस्थाओं तथा गाद के प्रबंधन एवं निस्तारण से संबंधित प्रक्रियाओं में विशेष रुचि दिखाई। यह जलाशयों की कार्यक्षमता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गुप्ता ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखने, गाद प्रबंधन को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा समग्र बुनियादी ढांचे के रख-रखाव के लिए अपनाए गए उपायों की समीक्षा की।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

बंगाल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बन रही है सरकार: नायब सिंह सैनी

सैनी ने किया पश्चिम बंगाल का दौरा, सैनी ने श्रीरामपुर विधानसभा में किया रोड शो

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बंगाल की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए बंगाल में चारों तरफ भाजपा की लहर चल रही है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान श्रीरामपुर विधानसभा के प्रत्याशी का नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने श्रीरामपुर विधानसभा के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर लोगों से भाजपा के समर्थन में वोट डालने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल के लोगों का शोषण किया है। बड़ी अपेक्षा के साथ लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी, लेकिन इस सरकार ने कम्युनिस्टों से भी ज्यादा अत्याचार किए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के लोगों ने अब मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार बनानी है बंगाल में ना रोजगार है, ना किसानों को एमएसपी पर फसल बिक रही है और न ही उचित मूल्य दिया जा रहा है। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने जिस प्रकार का ताण्डव किया है, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने घुसपैठियों को संरक्षण देने का कार्य किया है। इससे हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने को ठेस पहुंचाने का काम किया है। भ्रष्टाचार में फंसी हुई ममता सरकार स्वंय को साधारण होने का दिखावा करती है लेकिन उनकी सरकार में बड़े बड़े घोटाले हो रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीब लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। भाजपा सरकार ने अब तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है। भाजपा की नीतियों से गरीब व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की बहुत सारी जनहितैषी नीतियां हैं लेकिन पश्चिमी बंगाल में एक भी नीति को लागू नहीं किया गया। आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं राजनीतिक द्वेष के चलते बंगाल में लागू नहीं की गई। इसका परिणाम है कि बंगाल में और अधिक गरीबी बढ़ती जा रही है। जिसके चलते बंगाल के लोग ममता सरकार से निजात पाना चाह रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोड शो में लोगों का उत्साह एवं जोश देखने वाला बनता है। यहां के लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल का विकास चाहते है। बंगाल से उद्योगों का पलायन हो गया है। इसके अलावा युवाओं को भी रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बंगाल का युवा सरकार से आहत हैं और बंगाल में भय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में गरीब परिवारों के लोगों को मकान बनाकर दिए जा रहे है। देश के 80 करोड़ लोगों को भाजपा सरकार राशन पहुंचाने का काम कर रही है। विकसित भारत विकसित बंगाल के उद्देश्य से जनता भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का कार्य करेगी।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सोनीपत जिला कारागार के कैदियों के लिए कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम किया शुरू

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पुनर्वास आधारित न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने सोनीपत जिला कारागार के कैदियों के लिए कौशल विकास आधारित खाना पकाने की कला एवं भोजनालय संचालन में एक माह का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पहल पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री दीपक सिब्बल के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। यह जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य सचिव (हालसा पंचकूला) श्री जगदीप सिंह ने आज सोनीपत जिला कारागार में आयोजित कार्यक्रम में दी।

श्री जगदीप सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम सोनीपत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय और एसआरएम विश्वविद्यालय, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत के सहयोग से संचालित किया गया है। विश्वविद्यालय के विधि संकाय (लीगल एड सेंटर), होटल प्रबंधन संस्थान, प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग तथा विज्ञान एवं मानविकी विभाग की सक्रिय भागीदारी से इस पहल को मजबूती मिली है।

उन्होंने कहा कि एक माह की अवधि वाले इस पाठ्यक्रम में कैदियों को खाना पकाने की कला, रसोई प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, मेन्यू योजना और ग्राहक सेवा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता, लघु व्यवसाय विकास, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से जुड़े मॉड्यूल भी शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्र के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल कैदियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ अपराध की पुनरावृत्ति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और कानूनी साक्षरता का संयोजन कैदियों को एक नई दिशा प्रदान करता है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार करता है।

कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत के अध्यक्ष श्री जगजीत सिंह, सोनीपत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रचेता सिंह, एसआरएम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. वी. सैमुअल राज, विभिन्न संकायों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जेल प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला कर्मचारियों को एक वर्ष में 25 आकस्मिक अवकाश की मंजूरी

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- एमलिब टॉपर को मिलेगा डॉ. एस.आर. रंगनाथन अवॉर्ड
- कुवि में कार्यकारी परिषद की बैठक संपन्न, 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक मंगलवार को कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समिति कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक और नीतिगत प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करते हुए उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में पदोन्नति, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, सेवा विस्तार तथा अन्य प्रशासनिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे पहले 12 फरवरी 2026 को हुई कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई तथा उस पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसके बाद परिषद ने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिए। कार्यकारी परिषद ने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉ. रमेश कुमार दलाल को सीनियर प्रोफेसर के पद पर तथा केमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राजकमल को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई। संगीत एवं नृत्य विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. अशोक कुमार को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। वहीं आईआईएचएस के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर डॉ. अनिल गुप्ता के सीएएस के तहत प्रोफेसर पद के लिए पात्रता तिथि को पूर्व प्रभाव से लागू करने के संबंध में समीक्षा समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति दी गई।

आध्यात्मिक विकास समाज में रहकर निष्काम भाव से कर्त्तव्य निर्वहन में है: प्रो. असीम कुमार घोष

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- लोक भवन हरियाणा में राज्यपाल के निजी सचिव शंख चटर्जी द्वारा लिखित दो पुस्तकों, अद्वैत वेदांत-एक अनोखा दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण में धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र का विमोचन

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि आध्यात्मिक विकास संसार से दूर जाने में नहीं, बल्कि सजग होकर इसमें सक्रिय भागीदारी करने और निष्काम भाव से अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में है। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने यह बात आज लोक भवन हरियाणा में उनके निजी सचिव शंख चटर्जी द्वारा लिखित दो पुस्तकों अद्वैत वेदांत-एक अनोखा दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण में धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र का विमोचन करते हुए कही।

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि अद्वैत वेदांत और कुरुक्षेत्र, जिसे धर्मक्षेत्र के रूप में पूजनीय माना जाता है, दोनों ही मानवता के आध्यात्मिक विकास के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अद्वैत वेदांत, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया, हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना एक ही हैं। यह अलगाव के भ्रम को समाप्त कर साधक को आत्म-साक्षात्कार और आंतरिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करता है। कुरुक्षेत्र, जो महाभारत के भीतर भगवद्गीता का पवित्र युद्धक्षेत्र है, मानव जीवन में निहित नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है। यहीं भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को शाश्वत ज्ञान प्रदान किया और उन्हें धर्म, वैराग्य और स्पष्ट उद्देश्य के साथ कर्म करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि यह पुस्तकें न केवल बौद्धिक विमर्श को समृद्ध करेंगी, बल्कि पाठकों को जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिक समझ के गहरे आयामों पर विचार करने के लिए प्रेरित भी करेंगी। अद्वैत वेदांत एकत्व के दार्शनिक सत्य को प्रस्तुत करता है, जबकि कुरुक्षेत्र वह व्यावहारिक मंच है जहाँ इस सत्य को कर्म के माध्यम से साकार करना होता है।

राज्यपाल ने पुस्तकों के लेखक और अपने निजी सचिव श्री शंख चटर्जी की बुद्धिमता, समर्पण और सरल व्यवहार की सराहना करते हुए उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि शंख चटर्जी ने अपने माता-पिता से एक समावेशी बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण विरासत में पाया है, जो उनके विचारों और विशेष रूप से आध्यात्मिक विषयों को देखने के उनके नजरिए को समृद्ध बनाता है।

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि पुस्तकें हमें जीवन के उद्देश्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। पुस्तकें ही हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं और जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं वह शंख चटर्जी जैसे सृजनशील युवाओं के माध्यम से ही संभव होगी। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र के लिए प्राचीन संस्कृति और नवीन सोच को साथ लेकर चलने वाले युवाओं की बहुत आवश्यकता है।

श्री हरविंद्र कल्याण ने कहा कि आज लोकार्पित हुई इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति की लौ जलाने का कार्य हुआ है। हर युवा में यह सोच जगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने पूरी दुनिया को कर्म का संदेश दिया। इन पुस्तकों से पूरे समाज को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष की नई सोच और विजन से हरियाणा राज्य को नई दिशा मिल रही है। उनके कार्यों से हम सभी को असीम प्रेरणा मिलती है।

कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे रामकृष्ण मठ एवं मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी विमलात्मानंद महाराज ने कहा कि आज लोकार्पित हुईं दोनों ही पुस्तकें हिंदी साहित्य के खजाने को समृद्ध करेंगी।

संक्षिप्त-समाचार

जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप मेटासागा को डीआरडीओ के डेयर टू ड्रीम 5.0 इनोवेशन कांटेस्ट में दूसरा पुरस्कार

चंडीगढ़। जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर में इनक्यूबेटेड स्टार्टअप मेटासागा प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिष्ठित डेयर टू ड्रीम 5.0 इनोवेशन कांटेस्ट में स्टार्टअप और एमएसई (माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइज) श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह प्रतियोगिता भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) योजना के अंतर्गत आयोजित की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर का इनोवेशन चैलेंज उन अभूतपूर्व विचारों और प्रौद्योगिकियों को पहचानता है जिनकी रक्षा तथा सामरिक क्षेत्रों में संभावित अनुप्रयोग हो सकते हैं। विश्वविद्यालय में आईपीआर, इनोवेशन एवं इनक्यूबेशन/स्टार्ट-अप डिवीजन के प्रभारी प्रो. संजीव गोयल ने बताया कि मेटासागा पूरे देश के अनेक इनोवेटिव स्टार्टअप में से चुना गया। यह उपलब्धि जे.सी. बोस विश्वविद्यालय में विकसित उच्च गुणवत्ता वाले इनोवेशन और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को दशार्ती है। जे.सी. बोस टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, बुनियादी ढांचा, फंडिंग सहायता तथा उद्योग-अकादमिक संबंधों के माध्यम से पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पुरस्कार विश्वविद्यालय की नवाचार, उद्यमिता और राष्ट्रीय महत्व की प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने मेटासागा टीम तथा जे.सी. बोस टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियां विश्वविद्यालय में इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित करने के विजन को और मजबूत करती हैं, जो आत्मनिर्भर भारत तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देता है।

हरियाणा सरकार ने जारी किए 6 प्रशिक्षणाधीन आईएएस अधिकारियों के नियुक्ति आदेश

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 6 प्रशिक्षणाधीन आईएएस अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। अमितेज पांगटे को नूंह तथा मुस्कान श्रीवास्तव को फरीदाबाद में सहायक आयुक्त लगाया गया है। इसी तरह शिवानी पांचाल को कैथल, सोहम शैलेन्द्र को करनाल, विशाल सिंह को रोहतक तथा विवेक यादव को हिसार में सहायक आयुक्त लगाया गया है।

हरियाणा में एलपीजी, ईंधन आपूर्ति व्यवस्था सुचारू

चंडीगढ़। हरियाणा में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यभर में एलपीजी सिलेंडरों, जिनमें 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर भी शामिल हैं, की आपूर्ति तथा पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त भी शामिल हुए और जमीनी स्तर पर स्थिति का व्यापक आकलन किया गया। श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि प्रदेश का कोई भी परिवार स्वच्छ रसोई ईंधन की उपलब्धता से वंचित न रहे। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित अंतिम छोर तक एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडरों की उपलब्धता और पीएनजी कनेक्टिविटी की नियमित निगरानी की जाए। बुकिंग और वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए तथा खास तौर पर कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नए गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए तथा इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने यह निर्देश दिए कि वितरण व्यवस्था न केवल हर समय सतर्क रहे बल्कि संवेदनशील भी हो। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में रबी फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। गेहूं की निर्बाध आवक और खरीद सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

एलएनजेपी अस्पताल में फीनिक्स क्लब द्वारा दिया गया वाटर कूलर समाज के प्रति दायित्व: कीर्ति खोसला

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

दिन -प्रतिदिन बढ़ती गर्मी में मरीजों की परेशानियों और चिकित्सकों-कर्मचारियों की निःस्वार्थ सेवा को देखते हुए फीनिक्स क्लब द्वारा लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल को एक वाटर कूलर दान दिया गया है। इसे आपातकाल विभाग की दाईं तरफ स्थापित किया गया है।35000 की लागत से लगे इस वाटर कूलर के जल से प्रतिदिन अस्पताल में आने वाले करीबन 5000 लोगों को आने वाली भयंकर गर्मी की तीव्रता कम महसूस होगी और लोगों को प्यास बुझाने के लिए व्याकुल नहीं होना पड़ेगा। इस वाटर कूलर में आर.ओ. के माध्यम से शुद्ध एवं शीतल जल उपलब्ध होगा। इसके अलावा वाटर कूलर की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ व्यवस्था भी की गई है। यह कोई दान नहीं,बल्कि समाज की प्रति फीनिक्स क्लब का छोटा सा दायित्व है। यह कहना है क्लब के जिला अध्यक्ष कीर्ति खोसला का। वे आज परिसर में वाटर कूलर लगाने के उपरांत वहां उपस्थित रोगियों,अभिभावकों एवं अस्पताल के कर्मचारियों-अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। क्लब के सचिव दिनेश छाबड़ा ने इस अवसर पर कहा कि हर चीज के लिए शासन-प्रशासन के सामने गुहार लगाने की वजह लोगों को अपनी सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी समझकर आगे आकर समाज के लिए अपना योगदान देना होगा। सरकारी अस्पताल सभी की संपत्ति है और इसकी सुविधाओं को बेहतर बनाना हम सभी का कर्तव्य है। इस अवसर पर फीनिक्स क्लब के कोषाध्यक्ष दिनेश अनेजा, सदस्य अश्वनी अरोड़ा,गुरसेवक सिंह,जितेंद्र मेहता,दीवान भाटिया, डॉ.नीरज झांब, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ.तेजेंद्र सिंह चौहान, परामर्शक-फिजिशियन एवं हृदय-छाती रोग विशेषज्ञ रोग डॉ.शैलेंद्र ममगाईं शैली, डॉ.सुनिधि शर्मा, डॉ.समृद्धि शर्मा,वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सीमा शर्मा,नर्सिंग अधिकारी सुमन शर्मा,सोनिका शर्मा, पूनम सिंह, पूनम वर्मा,आयुर्वेदिक प्रशिक्षु सिमरन कौर, दीक्षांत मलिक, सामाजिक कार्यकर्ता ओनिश यथार्थ,ध्रुव शर्मा गायत्री ध्यानी, शिवा शर्मा और हेल्थ मैप संस्था के मैनेजर विकास शर्मा मौजूद थे।

मंडियों और खरीद केन्द्रों पर उठान कार्य पर विशेष फोकस रखें अधिकारी: विश्राम मीणा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र की मंडियों और खरीद केन्द्रों में अब तक 6.5 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। इस जिले में लगभग 1035 किसानों की बायोमेट्रिक हो चुकी है। इस सीजन में किसानों को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और उपमंडल स्तर पर एसडीएम को किसानों की समस्या और उनका समाधान करने की ड्यूटी भी लगाई गई है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा मंगलवार को लघु सचिवालय के एनआईसी कार्यालय में गेहूं खरीद कार्य को लेकर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि गेहूं खरीद कार्य के दौरान किसानों और व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और एचसीएस स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए। उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2026-27 के खरीद कार्य के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि गेहूं में काफी मात्रा में नमी है। इसलिए किसान गेहूं की फसल को सुखाकर लाए। उन्होंने कहा कि किसानों को गेट पास और बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान अपनी समस्या हैफेड या अन्य एजेंसियों के समक्ष रख सकते है। इन एजेंसियों के अधिकारी किसानों की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस सीजन में प्रशासनिक अधिकारियों का विशेष फोकस उठान कार्य पर रहेगा। सभी खरीद केन्द्रों पर उठान कार्य जल्द से जल्द करवाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी, डीएफएससी नरेश कुमार आदि उपस्थित थे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले की हर मंडी और खरीद केन्द्र पर पर्याप्त मात्रा में बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। इस जिले में 6 अप्रैल तक 1035 किसानों की बायोमेट्रिक हो चुकी है।

विकसित भारत 2047 के अनुरूप विकसित हरियाणा दस्तावेज तैयार: राव नरबीर सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश में विकसित हरियाणा दस्तावेज तैयार किया गया है। इस दस्तावेज के तहत सभी विभागों को वर्ष 2030, 2036 और 2047 को लक्ष्य मानते हुए अपने-अपने विजन, स्वरूप और चुनौतियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (ठउफ) विकसित भारत का केंद्र बिंदु रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं और मेक इन हरियाणा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिससे प्रदेश को औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कैपिटल सब्सिडी, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं को उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में दी जा रही 48,000 प्रति कर्मचारी की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी को बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त पंजाब के समय स्थापित किए गए सोनीपत, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला और पानीपत जैसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इन क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ की प्रारंभिक राशि से सक्षम फंड स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में किया है, जो स्वागत योग्य है।

हरियाणा में जलघरों में लगे फिल्टर की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करें अधिकारी : रणबीर गंगवा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने निर्देश दिए है कि पूरे हरियाणा में जलघरों में लगे फिल्टर की जांच की जाए। इस बारे में बकायदा प्रदेश के सभी एक्सईएन रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि गर्मियों के मद्देनजर पानी की व्यवस्था अभी से की जाएं, इसके तहत नहर बंदी के दौरान दिक्कत ना हो अभी से स्टोरेज और वैकल्पिक व्यवस्था पर फोकस करने के निर्देश भी दिए गए है।

मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने चंडीगढ़ सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की गर्मी में पेयजल आपूर्ति और बारिश के सीजन में निकासी संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में पब्लिक हेल्थ विभाग के ईआईसी श्री देवेंद्र दहिया, अन्य चीफ इंजीनियर भी मौजूद थे, जबकि प्रदेश भर से विभाग के एसई, एक्सईएन और एसडीओ वर्चुअल तौर पर जुड़े थे। श्री गंगवा ने विभाग की एक विस्तृत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2026-27 के लिए बजट में 20 प्रतिशत वृद्धि तथा संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) नीति को स्वीकृति मिलने पर मंत्री श्री रणबीर गंगवा का आभार भी व्यक्त किया। मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री गंगवा ने अधिकारियों को कहा कि जब भी वो अपने दौरे के वक्त किसी भी गांव में जाते है तो वहां के ग्रामीणों से पेयजल की सप्लाई और पानी निकासी के बारे में जरूर पूछते है। इसलिए शहरी ही नहीं, ग्रामीण एरिया में भी इस पर अधिकारी फोकस करें कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल हो। उन्होंने आने वाले गर्मी के मौसम के मद्देनजर बैठक में निर्देश दिए कि जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग एवं बिजली विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करते हुए नए ट्यूबवेल, बूस्टिंग स्टेशन एवं नहर आधारित जल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र चालू किया जाए, ताकि जनता को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जहां पानी की कमी है, वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विभाग की ओर से आधारभूत संरचना में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी के भंडारण, इनलेट चैनलों की स्थिति, फिल्टर बेड की सफाई, साफ पानी के टैंकों का रखरखाव एवं वितरण प्रणाली में लीकेज जैसी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। साथ ही, वाटर वर्क्स पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए चेतावनी बोर्ड एवं बैरिकेडिंग सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जेई/ऑपरेटिंग स्टाफ एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (श्हरउ) के सदस्यों के माध्यम से जल आपूर्ति की स्थिति की नियमित निगरानी की जाए तथा इसके लिए व्हाट्सएप समूह बनाकर सूचना का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायतों को नई संचालन एवं रखरखाव नीति के प्रति जागरूक करते हुए चरणबद्ध तरीके से एमओयू हस्ताक्षर करवाने के प्रयास किए जाएं, जिससे योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।

श्री गंगवा ने कहा कि जहां भी पानी की कमी की स्थिति उत्पन्न हो, वहां टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा टैंकर संचालन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।

संपादकीय

आईटी नियमों में बदलाव: डिजिटल न्यूज इकोसिस्टम को एक ढांचे में लाने की पहल

भारत में डिजिटल मीडिया का विस्तार जिस गति से हुआ है, उसने सूचना के पारंपरिक स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। आज खबरें केवल अखबारों या टेलीविजन तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स और ओटीटी माध्यमों के जरिए हर व्यक्ति तक तत्काल पहुंच रही हैं। इस तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य के बीच केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य पूरे डिजिटल न्यूज इकोसिस्टम को एकीकृत नियामक ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। यह पहल न केवल भारत के मीडिया क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है, बल्कि वैश्विक डिजिटल नियमन की दिशा में भी भारत की स्थिति को परिभाषित करेगी। वर्तमान समय में भारत का डिजिटल न्यूज इकोसिस्टम अत्यंत विविध और विकेंद्रीकृत है। बड़े मीडिया संस्थान जहां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से खबरें प्रसारित कर रहे हैं, वहीं स्वतंत्र पत्रकार, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स भी सूचना के प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। डिजिटल माध्यमों ने सूचना के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे आम नागरिक भी अपनी आवाज को व्यापक स्तर पर पहुंचा सकता है। हालांकि, इस खुलेपन के साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाएं, बिना सत्यापन के खबरों का प्रसार और ट्रोलिंग जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा एक सशक्त और स्पष्ट नियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित आईटी नियमों के तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है, जिससे उनकी पहचान और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही कंटेंट के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाने की संभावना है, ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म बिना जिम्मेदारी के जानकारी प्रसारित न कर सके। शिकायत निवारण तंत्र को भी अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की योजना है, जिससे यूजर्स को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट मंच मिल सके। इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सा कंटेंट किस आधार पर प्रमोट या हटाया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इस ढांचे में शामिल करने की तैयारी है, जिससे डिजिटल कंटेंट के सभी प्रमुख माध्यम एक समान नियमों के तहत संचालित हो सकें। यदि इन प्रस्तावित नियमों को वैश्विक संदर्भ में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि भारत का दृष्टिकोण एक संतुलित मॉडल की ओर बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट के माध्यम से बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। वहां यूजर्स के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और प्लेटफॉर्म्स को यह स्पष्ट करना होता है कि वे कंटेंट को कैसे मॉडरेट करते हैं। दूसरी ओर, अमेरिका में डिजिटल मीडिया के लिए कोई एकीकृत कानून नहीं है और वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। सेक्शन 230 के तहत प्लेटफॉर्म्स को यूजर-जनरेटेड कंटेंट के लिए सीमित जिम्मेदारी दी गई है, जिससे वे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। इसके विपरीत, चीन में डिजिटल मीडिया पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण है, जहां कंटेंट पर सख्त सेंसरशिप लागू होती है और सूचना का प्रवाह पूरी तरह से नियंत्रित रहता है। इन वैश्विक मॉडलों की तुलना में भारत एक मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश कर रहा है। यहां न तो पूरी तरह से खुला मॉडल अपनाया जा रहा है और न ही अत्यधिक नियंत्रित व्यवस्था, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी संरक्षित रखे। हालांकि, इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं होगा। यदि नियम अत्यधिक कठोर हुए, तो स्वतंत्र पत्रकारिता और छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। छोटे न्यूज पोर्टल्स और स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जटिल नियमों का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे डिजिटल मीडिया की विविधता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, यदि नियमन बहुत ढीला रहा, तो फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं की समस्या और बढ़ सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार एक ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाए, जिसमें न केवल नियंत्रण हो, बल्कि सहयोग और संवाद को भी प्राथमिकता दी जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि नए आईटी नियमों को लागू करने से पहले व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसमें मीडिया संगठनों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो। इससे एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा सकेगा जो व्यावहारिक, प्रभावी और सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य हो। ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन नियमों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होगा। जहां एक ओर कंटेंट की गुणवत्ता और जिम्मेदारी में सुधार हो सकता है, वहीं रचनात्मक स्वतंत्रता पर भी असर पड़ने की आशंका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे न केवल नियमों का पालन करें, बल्कि यूजर्स के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान करें। यह एक जटिल संतुलन है, जिसे बनाए रखना भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अंततः, आईटी नियमों में प्रस्तावित बदलाव भारत के डिजिटल मीडिया परिदृश्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। यह पहल जहां एक ओर डिजिटल मीडिया को अधिक संगठित, पारदर्शी और जवाबदेह बना सकती है, वहीं दूसरी ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित रखने की चुनौती भी प्रस्तुत करती है। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह वैश्विक अनुभवों से सीख लेते हुए एक ऐसा मॉडल विकसित करे, जो न केवल प्रभावी हो बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप भी हो। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस संतुलन को किस प्रकार साधती है और डिजिटल मीडिया के भविष्य को किस दिशा में ले जाती है।

उच्च शिक्षा और अनुसंधान की चुनौतियां

गिरीश्वर मिश्र (हि.स)

आज विकसित और प्रगतिशील देशों में शोध पर बड़ा बल दिया जाता है। वहाँ शिक्षा और शोध पर काफी खर्च होता है और शोध गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरता है। ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उन देशों की वैश्विक पहचान है। पड़ोसी देश चीन की शोध में प्रगति आशातीत रूप से उल्लेखनीय है जहाँ आज अनेक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय हैं। भारतीय संदर्भ में शोध की स्थिति आज दयनीय हो रही है हालांकि यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तब थे जब अन्यत्र इसकी कल्पना भी नहीं थी। आज हम शिक्षा और शोध में पिछड़ गए हैं। न बजट में प्रावधान है और न शिक्षा संचालन व्यवस्था ही संतोषजनक है।

शिक्षा में हमने इतने तरह के स्तरीकरण कर रखे हैं कि भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन कठिन है। आज कई तरह के निजी, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित, राज्य शासन द्वारा संचालित, अर्ध सरकारी, डीम्ड आदि अनेक किस्म के एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा के अनेक संस्थान और हजारों महाविद्यालयों का विशाल संजाल तो खड़ा है परंतु अध्यापकों और शिक्षा के लिए जरूरी संसाधनों का अधिकांश शिक्षा केंद्रों पर घोर अभाव है। सरकारी संस्थाओं की स्थिति यदि व्यवस्थागत पेचीदगी का शिकार होकर असंतोषजनक है तो निरंकुश निजी शिक्षा संस्थान व्यापार के तर्ज पर भारी शुल्क उगाही कर मुनाफा कमा रहे हैं।

शोध की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय कई अर्थों में सार्वभौमिक होते हैं। उनके सिद्धांत बहुत हद तक ऐसी सामग्री से जुड़े होते हैं जो स्थिर होती हैं और उनको लेकर सामान्यीकरण की अधिक संभावना होती है। उनका ज्ञान बहुत हद तक संचयी प्रकृति का भी होता है। ज्ञान पाने वाला और ज्ञान की वस्तु में स्पष्ट भेद होता है- वैज्ञानिक चेतन प्राणी है और पदार्थों की दुनिया उससे भिन्न होती है। प्राकृतिक विज्ञानों के ज्ञान को पृथ्वी पर हर कहीं एक ही कसौटी पर मापा, जांचा और परखा जा सकता है (अन्तरिक्ष और दूसरे ग्रहों की बात जरूर भिन्न है)। दूसरी तरफ मानविकी और समाज विज्ञान का स्वभाव भिन्न है। इनके विषय समाज, संस्कृति, परंपरा, आदर्श और मूल्य जैसे मानवीय सरोकारों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और उनमें अध्येता और विषयवस्तु दोनों मनुष्य होते हैं।

पश्चिम में समाज विज्ञानों के पुरोधाओं ने प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर विज्ञान की ही विधि को अपने विषय में लागू किया। विज्ञान कहलाने के लोभ में मानव व्यवहार और मानव समाज को 'वस्तु' मान कर अध्ययन शुरू हुआ। यद्यपि सामाजिक विज्ञान परिस्थिति सापेक्ष्य ज्ञान ही दे पाते हैं और अध्ययन विषय भी देश काल के साथ बदलता रहता है।

इसलिए अब गुणात्मक, आख्यानपरक और निर्वाचन की पद्धतियों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। फिर भी व्यापकि स्वीकृति इंद्रियानुभविक विधि, मापन और सांख्यिकी के विश्लेषण की है। इनकी सहायता से एक सुगम परिपाटी चल पड़ी। अब विधि की जरूरतों को पूरा कर पीएचडी की उपाधि त्वरित गति से अर्जित होने लगी। शोध सिर्फ. शोध के लिए किया जाने लगा न कि ज्ञान वृद्धि या किसी समस्या के समाधान के लिए। मानविकी में शोध अधिकाधिक वर्णनात्मक होते गए और उसे भी कुछ ढर्रों पर चला दिया गया। शोध की मौलिकता, देशज ज्ञान से रिश्ता, सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ाव और उपयोगिता के सरोकार लगातार उपेक्षित होते गए।

भारत की देशज ज्ञान परंपरा विशाल है और उसमें शोध और अनुसंधान की व्यवस्था है। न्याय-शास्त्र 'प्रमाण' यानी अध्ययन विधि की ही चिंता करता है।

हमारे विश्वविद्यालयों में शोध का आरम्भ औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा किया गया। यूरोप और अमेरिका के सिद्धांतों, विचारों और विधियों का प्रभुत्व ऐसा रहा कि भारतीय विश्वविद्यालयों में समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों में विदेशी ज्ञान का वर्चस्व हो गया। आज भी अधिकांश विषयों की पाठ्य पुस्तकें और ज्ञान की सामग्री उसी तरह की है। भारतीय समाज उतना ही प्रासंगिक होता है जितना आंकड़ों को पाने के लिए जरूरी है। ऐसा ज्ञान न पश्चिमी देशों के काम का होता है न अपने देश के। ऐसे में दुहराव तथा पिश्टपेषण का बोलबाला हो रहा है।

इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि भारतीय शोध कार्यों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में कमतर है। इन शोध कार्यों की उपयोगिता, प्रमाणिकता और ज्ञान में योगदान बड़ा ही सीमित है। इसलिए प्राध्यापक वर्ग, नीतिनिर्धारकों और शोध के उपभोक्ताओं की चिंता जायज है।

जनसंख्या बढ़ने के साथ शिक्षा संस्थानों की संख्या तो जरूर बढ़ी है परंतु उनकी गुणवत्ता में गिरावट चिंता का कारण है। संस्थानों की कार्य-संस्कृति पर राजनीति हावी है। शिक्षा केंद्र में अकादमिक कार्य, वैचारिक प्रयास और सृजनशीलता की जगह उत्सवप्रियता का अतिरेक है जिससे क्षणिक उत्तेजना और संतुष्टि तो मिलती है परंतु अध्ययन-अध्यापन हाशिये पर चला जा रहा है। शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और विचार-विमर्श के वातावरण से विवेकवान समालोचक की दृष्टि लुप्त हो रही है। वार्ता, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ की जगह अनुकीर्तन से ज्ञान में वृद्धि की आशा व्यर्थ है।

तमाम दबावों के बीच हमारे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले शोध की मान्यताओं और प्रतिष्ठा के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पा रहे हैं। शोधार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है पर उसी के साथ शोध से जुड़े नैतिक प्रश्न उलझते जा रहे हैं। साहित्य चोरी (प्लैग्रिज्म) की घटनाएँ बढ़ रही हैं, शोध निदेशकों द्वारा शोषण की घटनाएँ भी हो रही हैं। व्यवस्था की कमजोरी के चलते शोध कार्य में पारदर्शिता में घट रही है। शोध कार्य एक कृत्य (रिचुअल) का रूप लेता जा रहा है जिसमें कोल्हू के बैल की तरह बँधी-बंधाई लीक पर चलना ही शोध की पद्धति बनती जा रही है। जिज्ञासा, प्रश्नाकुलता और कल्पनाशीलता पिछड़ रही है। इसका कारण संसाधनों और सुविधाओं का अकाल तो है पर उसका समुचित वितरण न होना भी क्षोभ का कारण बन रहा है।

यह भी एक बिडंबना है कि जिस भारत में ज्ञान को पवित्र और क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया वहाँ आईआईटी जैसे उच्च संस्थानों में मानसिक रुग्णता और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। अनुशासित जिज्ञासा से शोध का आरंभ होता है और ज्ञान के संधान के साथ यह यात्रा आगे बढ़ती है। कहा गया है- विद्या से विनय और विनय से पात्रता, फिर पात्रता से समृद्धि और तब सुख मिलता है। आज इस सूत्र को फिर से दुहराने और अपनाने की जरूरत है।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति हैं।)

भारत की विकास गाथा के केंद्र में महिलाएँ

श्रीमती विजया रहाटकर

भारत की विकास गाथा को अक्सर संख्याओं, विकास दरों, अवसंरचना विस्तार और आर्थिक उपलब्धियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन,पिछले दशक का सबसे बड़ा बदलाव आँकड़ों से परे है। यह एक गहरे सामाजिक बदलाव में परिलक्षित होता है– महिलाओं का केवल भागीदारके रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाले अग्रिम व्यक्तियों के रूप में उभरना।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर यहबदलाव न तो आकस्मिक है और न ही अलग-थलग है। यह एक सोच-समझकर किये गये सतत प्रयास का परिणाम है, जो जीवन के हर चरण में महिलाओं को समर्थन देने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करता है। लड़की के जन्म से लेकर उद्यमी, पेशेवर, या सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में उसकी यात्रा तक, यह दृष्टिकोण समग्र, सतत और परिवर्तनकारी रहा है।

राजनीतिक भागीदारी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 12,14,885 है, जिनकी कुल 24,41,781 निर्वाचित प्रतिनिधियों में हिस्सेदारी 49.75% है–इस प्रकार, महिलाएँ जमीनी स्तर पर शासन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इस क्रम में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी उपलब्धि है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। यह उच्च विधायी क्षेत्रों में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने में राष्ट्र की अडिग प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इस ऐतिहासिक सुधार की वास्तविक क्षमता केवल इसके प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। अधिनियम की प्रावधानों को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की आवाज को सिर्फ मान्यता ही न मिले, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना में इसे संस्थागत रूप से समाहित किया जा सके।इसके जल्द लागू होने से न केवल समावेशी शासन को गति मिलेगी, बल्कि यह बेहतर प्रतिनिधित्व और न्यायसंगत राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा।

दशकों तक, लैंगिक पक्षपात ने भारत के जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतकों को प्रभावित किया। आज, वह कहानी धीरे-धीरे फिर से लिखी जा रही है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसी पहलों ने गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकताओं को चुनौती देने और लड़की के मूल्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5)में दिखाई देता है, जिसमें 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का लैंगिक अनुपात दर्ज किया गया है, जो सिर्फ संख्यात्मक सुधार ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी संकेत देता है। 'मिशन इंद्रधनुष' जैसे कार्यक्रम जीवन के प्रारंभिक चरण में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करते हैं। 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी','पोषण 2.0', तथा 'पोषण अभियान' के प्रयास कुपोषण का समाधान करते हैं–यह मानते हुए कि स्वस्थ बचपन, सशक्त वयस्कता की ओर पहला कदम होता है।

माताओं के लिए, संस्थागत समर्थन में काफी विस्तार हुआ है। पीएमएमवीवाई के तहत, 4.28 करोड़ से अधिक महिलाओं को 20,149 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गयी है, जो गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महिलाएं केवल भाग ही नहीं ले रही हैं–वे नेतृत्व भी कर रही हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में संस्थापक और निर्णयकताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका में लगातार वृद्धि हो रही है और वे नवाचार और उद्यम में भी योगदान दे रही हैं। इस परिवर्तन में वित्तीय समावेश ने अहम भूमिका निभाई है। पीएमएमवाई के तहत, 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 57.79 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं, जिनमें लगभग 66% लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रत्येक ऋण केवल वित्तीय सहायता का ही नहीं, बल्कि महिलाओं की आकांक्षाओं में विश्वास का भी प्रतीक है। इसके पूरक रूप में, जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेश और गहरा हुआ है, जिसके अंतर्गत 57.93 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 32.29 करोड़ (55.7%) महिलाओं के हैं।

जमीनी स्तर पर, परिवर्तन का पैमाना और भी अधिक प्रभावशाली है। लगभग 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिकस्वयं-सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे सामूहिक सहनशीलता, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला है। इस इकोसिस्टम ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया हैऔरस्वयं सहायता समूहों को 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 84 लाख ग्रामीण महिलाएं उद्यमी बन चुकी हैं, जबकि 5 करोड़ महिला किसानों ने उन्नत और सतत कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं।

स्वाभाविक रूप से अगला सवाल उठता है–क्या सशक्तिकरण,आजीविका से समृद्धि की ओर बढ़ सकता है? लखपति दीदी जैसी पहलों का लक्ष्य आय सृजन को मजबूत करना है, जबकि ड्रोन दीदी पहल, जिसका लक्ष्य 15,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना है, एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है–ग्रामीण महिलाओं को प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि इकोसिस्टम में एकीकृत करना।

सशक्तिकरण का मतलब रोजमर्रा के बोझ को आसान बनाना भी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.56 करोड़ से अधिक धुँआ-रहित रसोई घरों ने स्वास्थ्य में सुधार किया है और कठिनाइयों को कम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण ने गरिमा और सुरक्षा में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी 73% लाभार्थी महिलाएं हैं, के तहत निर्मित घरों ने स्वामित्व और सुरक्षा को मजबूत किया है। साथ मिलकर ये सभी पहलें दैनिक जीवन में गरिमा की परिभाषा को नए सिरे से स्थापित करती हैं।

इसके साथ ही, महिलाएं उन स्थानों में भी प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें कभी उनकी पहुँच से बाहर माना जाता था। सशस्त्र बल इस बदलती हुई वास्तविकता को दशार्ते हैं, जहाँ महिलाएँ नेतृत्व और जिम्मेदारी की भूमिकाएँ निभा रही हैं, जिसमें युद्ध क्षेत्र भी शामिल हैं। सवाल अब यह नहीं है कि महिलाएँ सेवा कर सकती हैं या नहीं, बल्कि यह है कि वे कितनी दूर तक नेतृत्व कर सकती हैं।

कार्यस्थल सुधारों ने भी इस बदलाव में योगदान दिया है। नयी श्रम संहिताएँ महिला कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपायों के साथविभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें रात की शिफ्ट भी शामिल है, काम करने में सक्षम बनाकर समावेश को बढ़ावा देती हैं। ये संहिताएँ समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान पर जोर देती हैं–सुरक्षा से सशक्तिकरण की ओर बदलाव को रेखांकित करती हैं।

संस्थागत समर्थन एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शिकायत निवारण से आगे बढ़कर सक्रिय जुड़ाव और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी अपना विस्तार किया है।'शी सर्व्स' जैसी पहल महिला अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करती हैं, जबकि 'यशोदा एआई' उन्हें उभरते तकनीकी कौशल प्रदान करती है। 'कैंपस कॉलिंग' युवाओं में जागरूकता बढ़ाता है, 'शी इज अ चेंज मेकर' कार्यक्रम जमीनी स्तर पर नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता हैऔर 'महिला जनसुनवाई' सुलभ शिकायत निवारण सुनिश्चित करता है।

जो उभरकर सामने आता है, वह प्रयासों का एक शक्तिशाली समन्वय है, जो महिला-नेतृत्व वाले विकास के नए युग को आकार दे रहा है।

(लेखिकाराष्ट्रीय महिला आयोगकीअध्यक्षहैं)

आज का राशिफल

मेष: आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। आपके अधिकांश कार्य सहज रूप से पूरे होते नजर आएंगे। हालांकि, अनजान लोगों से अधिक निकटता बनाने से बचें, वरना समय की बबार्दी हो सकती है। मित्रों के साथ व्यापारिक विषयों पर चर्चा संभव है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: पुराने विवाद आज फिर से उभर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपकी अच्छी सलाह को भी लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, इसलिए बिना मांगे सुझाव देने से बचें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना ही बेहतर रहेगा। विशेष रूप से महिलाएं रसोई में सावधानी बरतें। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आज कार्यक्षेत्र में अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपके कई जरूरी काम समय से पहले पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और सामाजिक दायरा मजबूत होगा। थोड़े तनाव के बावजूद आपकी कार्यक्षमता प्रभावित नहीं होगी और प्रदर्शन अच्छा रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में उलझनें आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ विरोधी आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

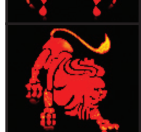
सिंह: आज आप घर के वातावरण में ही सुकून महसूस करेंगे। प्रेमी या जीवनसाथी को कोई खास उपहार देकर रिश्तों में मिठास ला सकते हैं। अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए संतुलित आहार और योग को दिनचर्या में शामिल करें। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: जिस कार्य को आप आसान समझ रहे थे, वह आज चुनौतीपूर्ण बन सकता है। रिश्तेदारों के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। बातचीत में संयम रखें और कठोर शब्दों से बचें। विद्यार्थियों को करियर को लेकर अधिक गंभीर होने की जरूरत है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। दोपहर के बाद कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन किसी भी काम को केवल औपचारिकता के तौर पर न करें। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आज आपके विरोधी कमजोर पड़ते नजर आएंगे, जिससे आपको राहत मिलेगी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए कार्यों की योजना बना सकते हैं। जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाएंगे। जरूरी कार्यों को सुबह के समय निपटाना अधिक लाभकारी रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

धनु: दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और सामंजस्य मजबूत होगा। नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। लंबे समय से रुके कार्य फिर से शुरू होंगे। आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा। पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपके लिए लाभकारी रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मकर: आज कार्यभार अधिक रहेगा और एक ही काम को बार-बार करना पड़ सकता है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण फैसलों को कुछ दिनों के लिए टालना उचित रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: कार्यस्थल पर मनचाहा काम मिलने से संतुष्टि महसूस होगी। सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव संभव है। आर्थिक मामलों के लिए दिन अनुकूल है और विवादित मामलों में सफलता मिल सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

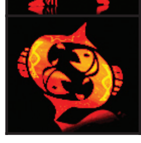
मीन: आज किसी जरूरी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। अपनी रुचि के अनुसार काम करने के अवसर मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। राजनीति या सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। *(सिटी दर्पण)*

योग परम स्वास्थ्य

हृदयनारायण दीक्षित
(हि.स)

अनुशासनविहीन जीवन में स्वस्ति और लोकमंगल नहीं होते। प्रकृति स्वयं अनुशासन में गतिशील है। मनुष्य के लिए इसी अनुशासन का पालन उपयोगी दिनचर्या है। इसका सम्बंध स्वस्थ मन से है। स्वस्थ बुद्धि से है और निर्मल आत्मा से भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मस्त व्यक्तित्व के धनी हैं। उच्च कोटि के संसद विज्ञ, 5 बार के सांसद व दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। व्यवहार में अनुशासित अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित जनप्रिय राजनेता हैं। योगी हैं। सो, अनुशासन में रहते हैं। और अपने परिचितों से भी अनुशासित रहने की अपेक्षा करते हैं। वे हमारे प्रति शुभेक्षु हैं। हमलोग भिन्न-भिन्न विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। वे योग विज्ञानी भी हैं। योग का हमारा ज्ञान किताबी है, लेकिन उनका ज्ञान अनुभव अनुभूति और व्यवहारिक जीवन से भरा पूरा है।

चार दिन पहले आकाशवाणी का 89वाँ स्थापना वर्ष मनाया गया था। उसमें पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों को सम्मानित किया गया था। आकाशवाणी के वरिष्ठ महानुभाव भी सम्मानित किए गए थे। पद्मश्री में मेरा भी नाम था। योगी जी ने उस कार्यक्रम में मेरी दिनचर्या पर चर्चा की। उन्होंने कुछ पुरानी बातें खोलीं और याद कराया कि हमारी दिनचर्या अनुशासित नहीं थी। उन्होंने मुझे याद कराया की देर रात तक जागना स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता। मैंने उनसे बताया कि दिनभर राजनीतिक कारणों से व्यस्तता रहती है और रात में लिखने-पढ़ने का समय मिलता है। उन्होंने हंसते हुए कहा था कि यही दिनचर्या उलट दी जाए और सुबह जल्दी उठा जाए और रात्रि में जल्दी सोया जाए। इन्हीं पुरानी बातों को उन्होंने आकाशवाणी के कार्यक्रम में फिर से दोहराया।

दिनचर्या व्यक्तित्व का आधार है। दिनचर्या का अनुशासन प्रायः हमारा निर्णय होता है। इसमें थोड़ी-सी चूक भी क्षतिकारी होती है। दिनचर्या पर देशकाल का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडी जलवायु वाले देशों में शरीर के ताप को विशेष स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे देशों में अधिक ऊष्मा देने वाली दिनचर्या चलती है। आदर्श दिनचर्या पर प्राचीन भारत में अच्छा और परिश्रम हुआ है। अच्छी दिनचर्या में अच्छी नींद, अच्छा जागरण और अच्छे आहार की आवश्यकता होती है। उसे कालखंड में अन्न की विशेष महत्ता पर जोर दिया गया है। अन्य भौतिक पदार्थ है। प्राचीन अनुभूति में वह दिव्य है। तैत्तरीय उपनिषद के एक सुंदर मंत्र में कहते हैं, 'यह व्रत संकल्प है कि अन्न की निंदा न करें। अन्न ही प्राण है। प्राण ही अन्न है। शरीर भी अन्न है। शरीर और प्राण का अंतरसंबंध है। अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो यह जान लेता है उसकी दिनचर्या आदर्श हो जाती है।'

उपनिषद में कहते हैं कि, 'आहार का अर्थ अन्न है।' आहार साधारण खाद्य वस्तु नहीं है।

आहार का सम्बंध अनुशासित दिनचर्या से भी है। व्यापक अर्थों में अनुशासित दिनचर्या के पांच द्वार हैं। देखना भी एक आहार है। देखे गए दृश्य चित्र को प्रसन्न या अप्रसन्न करते हैं। सुंदर दर्शन में मन प्रसन्न होता है। अभद्र दर्शन में मन अप्रसन्न होता है। इसलिए देखने में भी संयम की आवश्यकता है। पढ़ना भी एक आहार है। अनुशासित दिनचर्या वाला ज्ञानवर्धक अध्ययन मन स्वस्थ रखता है। निराश करने वाली सूचनाएं कष्ट पहुंचाती हैं। इस समय आधी दुनिया युद्ध में है। समाचार माध्यमों में धुआं ही धुआं है। बारूदी वातावरण है। यह निराश करता है। गंध भी आहार है। किसी बाग या उपवन में गंधमादन हवा आती है। चित्त गंधमादन हो जाता है।

ज्ञानवर्धन सुना या रुचिपूर्ण सुनना, गीत सुनना काव्य सुनना, नदी के पास खड़े होकर नाद सुनना आनंददायक है। दुनिया का सारा ज्ञान देखने और सुनने से प्रकट हुआ है। वैदिक साहित्य सुना हुआ है। स्पर्श भी आहार है। किसी प्रियजन का स्पर्श आनंददाई है। दृश्य, श्रव्य, नाक, स्पर्श और रसना 5 द्वार हैं। इनसे हम कुछ न कुछ लिया करते हैं। जीवनचर्या के अनुशासन में इन पांचों द्वारों की भूमिका है।

भारतीय ज्ञान परंपरा में 10 दिशाएं हैं। काल गणना भी है। वासना भी जन्म और जीवन के साथ आई है। वासना का अनुशासन प्रार्थना है। जीवन ऊर्जा का अधोगामी प्रवाह वासना है। वासना भी एक दिशा है लेकिन इसका कार्यव्यवहार दुखदायी है। लोकमंगल के विपरीत भी है। जीवन ऊर्जा की दूसरी दिशा प्रार्थना है। वासना और प्रार्थना दोनों में ही हमारी चेतन ऊर्जा ही मुख्य कारक है। दोनों में स्वयं के प्रति आस्तिकता है। लेकिन प्रार्थना में प्रार्थना के प्रति गजब का विश्वास है। ऋग्वेद में प्रार्थना है-हे देवो! हमारा मन शुभ करो। यजुर्वेद में प्रार्थना है-तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु-हमारे मन को कल्याणकारी संकल्प से भरो। विरोधाभास ध्यान देने योग्य है। मन हमारा है, इसे शुभ या शिव बनाने की प्रार्थना हम दूसरे से क्यों करते हैं? प्रार्थना का अन्तर्भूत तत्त्व ऐसा नहीं है। कोई देवता प्रार्थना सुनकर हमारा मन ठीक करे या न करे लेकिन चित्त से उगी प्रार्थना हमारे चित्त के अणु-परमाणु को शिव तत्त्व से भर देती है।

मैंने हजारों निबन्ध लिखे हैं। कोई पूछे कि इन सबका आधारभूत तत्त्व क्या है? मैं उत्तर देता हूँ कि हमारा लेखन, भाषण और समूचा राजनैतिक कार्य व्यवहार प्रार्थना ही है। सिर्फ प्रार्थना ही। प्रार्थना है कि हिंसा से भरे स्वजन संवेदनशील हों।

पतंजलि का योग 'चित्तवृत्ति निरोध' है। श्रीकृष्ण का योग 'मनोनिग्रह' है। दोनों का मन्तव्य एक है। श्रीकृष्ण 'अभ्यास और वैराग्य' का मन्त्र देते हैं। पतंजलि की भाषा भी वही है 'अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः-अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का नियंत्रण संभव है।' (पतंजलियोगसूत्र 1.12) वे आगे अभ्यास की परिभाषा बताते हैं 'इन दो (अभ्यास, वैराग्य) में अभ्यास स्वयं में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने का प्रयास है-तत्रस्थितौ यत्नो अभ्यासः।' (वही 13) अभ्यास का संकल्प महत्वपूर्ण है। अभ्यास स्वयं के प्रति सजग चेष्टा है, वैराग्य इच्छा शून्यता है।

अभ्यास और वैराग्य चित्त को संयत करते हैं। योगासन और ध्यान इसी के उपकरण हैं। व्यक्तित्व की पूरी ऊर्जा को एकाग्र करने का नाम अभ्यास है। फिर वैराग्य बताते हैं, 'ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सजग प्रयास से भोग आसक्ति के प्रति वितृष्णा वैराग्य की प्रथम अवस्था है, पुरूष के अंतरतम का बोध होने पर सभी इच्छाओं का विलीनीकरण वैराग्य की पूर्णता है।' (वही 15 व 16) श्रीकृष्ण ने कहा, 'असंयत के लिये योग कठिन है, लेकिन संयत व्यक्ति संकल्पबद्ध होकर योगलब्ध हो जाता है।' (गीता 6.36)

पतंजलि योग सूत्रच में दर्शन के आत्मिक अनुभव में मन की चंचलता बाधा है। बाधाएं और भी हैं। पतंजलि ने योग सूत्र (30) में बताया है कि 'रोग, प्राणहीनता, संशय, प्रमाद, आलस्य, आसक्ति, भ्रान्ति और अस्थिरता बाधाएं हैं। दुख, निराशा, कपकपी और अनियमित श्वसन लक्षण हैं।' यहां 'रोग' ध्यान देने योग्य हैं। पतंजलि वैद्य या चिकित्सक नहीं थे। चरक संहिता आयुर्विज्ञान का प्रख्यात ग्रंथ है। बताते हैं-'बिना रोग का होना सुख है और रोग दुख है।' आगे स्वास्थ्य के बारे कहते हैं 'जब मन और बुद्धि का समान योग रहता है तब मनुष्य स्वस्थ रहता है जब इनका अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होता है तब रोग।'

रोग मन और बुद्धि के अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग के परिणामी है। योग परम स्वास्थ्य है। प्राण और शरीर का योग जीवन है। प्राण का कम होना जीवनी शक्ति का घटना है। आलस्य प्राण शक्ति घटाता है, आसक्ति बढ़ाता है।

पतंजलि ने मनुष्य का रहस्यपूर्ण विवेचन किया है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्म से स्वस्थ व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता। आनंदित व्यक्ति सृजन करता है और तनावग्रस्त व्यक्ति ध्वंस। योग तनावग्रस्त विश्वमानवता को भारत का प्रशांत उपहार है। लेकिन योग का विज्ञान पढ़ने से ही समझ में नहीं आता। यह पठनीय कम करणीय ज्यादा है। लेकिन हमारी लत है कि पठन पाठन ही ज्यादा है, करणीय कम।

(लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

पंजाब का आबकारी राजस्व लक्ष्य को पार करते हुए 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँचा; चार वर्षों में वसूली लगभग दोगुनी: हरपाल सिंह चीमा

वित्तीय वर्ष 2025-26 की वसूली संशोधित लक्ष्य से 582 करोड़ रुपये अधिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी 207 खुदरा शराब समूहों का सफल आवंटन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ घोषणा की कि आबकारी एवं कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ठोस आबकारी नीति उपायों और कुशल प्रशासनिक कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने बताया कि 11,200 करोड़ रुपये के संशोधित आबकारी राजस्व लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 31 मार्च, 2026 तक सफलतापूर्वक 11,782 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो लक्ष्य से 582 करोड़ रुपये अधिक हैं।

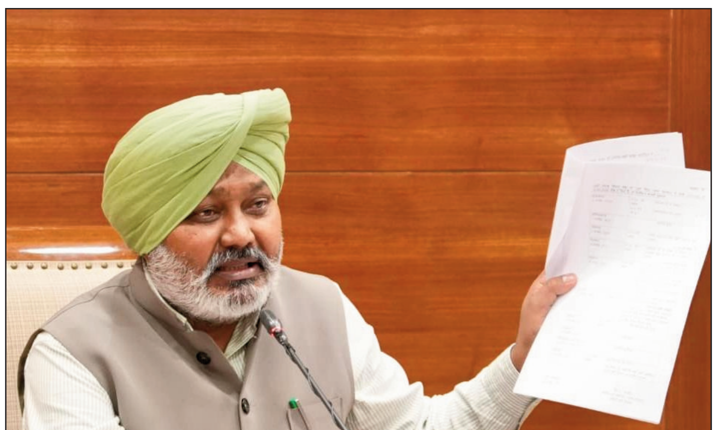

व्यापक वित्तीय उपलब्धियों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने इस सफलता का श्रेय सीधे तौर पर राज्य सरकार के सक्रिय शासन और व्यापार-हितैषी नीतियों को दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, विशेष रूप से, पिछले चार वर्षों में आबकारी राजस्व लगभग दोगुना हो गया है, जो 6,254.84 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,782 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह उपलब्धि पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए राजस्व अधिकतम करने के प्रति विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

आगामी वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने रणनीतिक वित्तीय लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी नीति 10,520 करोड़ रुपये के अनुमानित लाइसेंस शुल्क लक्ष्य के साथ तैयार की गई है, जबकि वर्ष 2025-26 में यह 9,877 करोड़ रुपये था। यह उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 207 खुदरा शराब समूह वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जो राज्य सरकार की आबकारी नीति में लाइसेंसधारकों के विश्वास को दर्शाता है। आबकारी नीति 2026-27 को समग्र रूप से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, जिसने राज्य के खजाने में राजस्व के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के साथ-साथ शराब व्यापार में स्थिरता सुनिश्चित की है।

राज्य के राजस्व स्रोतों में लगातार हो रही वृद्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भविष्य की रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भविष्य की ओर देखते हुए, आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी कुल राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। पंजाब सरकार राजस्व संग्रह और नियामक दक्षता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, मजबूत प्रवर्तन, बेहतर अनुपालन प्रणालियों और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारी यूनियनों के साथ मांगों के समाधान को लेकर की बातचीत

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों की शिकायतों संबंधी कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कर्मचारी यूनियनों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य संबंधित यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों को आ रही समस्याओं और उनकी मांगों का समाधान करना था। करीब दो घंटे तक चली इन बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने यूनियन नेताओं द्वारा प्रस्तुत मांगों और मुद्दों को सहानुभूति के साथ विस्तार से सुना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने संबंधित सरकारी विभागों के उपस्थित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए। इसके अलावा उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे संबंधित यूनियनों के साथ विशेष फॉलो-अप बैठकें करें, ताकि उनके विशिष्ट मुद्दों का तेज, प्रभावी और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

भगवंत मान सरकार ने 70 पदों पर सीधी भर्ती को दी मंजूरी, योजना विभाग को किया मजबूत और रोजगार के नए अवसर सृजित: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

राज्य में रोजगार सृजन और प्रशासनिक दक्षता को बड़ा बढ़ावा देते हुए पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज योजना विभाग में 70 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है।

सांख्यिकी निदेशालय में 68 पद भरे जाएंगे, जिनमें 14 सहायक अनुसंधान अधिकारी, 4 वरिष्ठ सहायक और 50 इन्वेस्टिगेटर शामिल

यहां जारी एक प्रेस बयान में यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि दो प्रमुख संस्थाओं—सांख्यिकी निदेशालय तथा आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड—के अधीन विभिन्न ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने की औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है।

स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कुल 70 रिक्त पदों में से 68 पद सांख्यिकी निदेशालय में भरे जाएंगे। इनमें 14 सहायक अनुसंधान अधिकारी, 4 वरिष्ठ सहायक और 50 इन्वेस्टिगेटर की सीधी भर्ती शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि शेष 2 पद आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड को आवंटित किए गए हैं, जिनमें एक ग्रुप-ए प्रोग्रामर और एक वरिष्ठ सहायक की भर्ती की जाएगी।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभ में पंजाब कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें इन दोनों संस्थाओं में विभिन्न श्रेणियों के तहत 140 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि 29 मार्च 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रस्तावित पदों में से 50 प्रतिशत पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिससे वर्तमान भर्ती अभियान के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या 70 हो गई।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस संशोधित प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति के बाद अब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (एसएसबी) को औपचारिक पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसएसबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन महत्वपूर्ण पदों को शीघ्र तथा पारदर्शी तरीके से भरा जा सके।

अब बागबानी क्षेत्र को मिलेगी नई रफ्तार, मोहिंदर भगत द्वारा बड़े पैमाने पर फलदार पौधे तैयार करने के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज बागबानी विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए बागबानी क्षेत्र को नई रफ्तार देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकारियों को निर्देश दिए कि फलदार पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि फलों के लिए मार्केट की मांग और किसानों की सुविधा के अनुसार ही फलदार पौधों की पौध तैयार की जाए।

इस बैठक के दौरान बागबानी विभाग के सचिव श्री अरशदीप सिंह थिंद और डायरेक्टर श्री मनीष कुमार ने विभाग के विभिन्न प्रोजेक्टों की प्रगति के बारे में मंत्री को जानकारी दी। इस मौके पर विभाग में नई भर्ती और अधिकारियों की प्रमोशन संबंधी भी विशेष चर्चा की गई।

इस अवसर पर बागबानी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में बागबानी क्षेत्र को प्रफुल्लित करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जिका) के सहयोग से लगभग 1300 करोड़ रुपये के मंजूर प्रोजेक्टों की लगातार पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पंजाब में मौसम परिवर्तन के अनुकूल और उच्च मूल्य वाली बागबानी फसलों को प्रोत्साहित करना है।

संक्षिप्त-समाचार

बैसाखी पर पाकिस्तान ने भारत के 2800 से अधिक तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया

नई दिल्ली। बैसाखी के अवसर पर पाकिस्तान ने इस वर्ष भारत के 2800 से अधिक तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है। दल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने मंगलवार को बताया कि बैसाखी पर्व के अवसर पर भारत से 2800 से अधिक तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किए गए हैं, ताकि वे 10 से 19 अप्रैल 2026 तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले वार्षिक धार्मिक समारोह में भाग ले सकें। उल्लेखनीय है कि खालसा साजना दिवस यानी बैसाखी के पवित्र अवसर पर हर वर्ष भारत से सिख श्रद्धालुओं के जत्थे पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाते हैं। इस यात्रा का आयोजन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाता है, जो श्रद्धालुओं की यात्रा और व्यवस्थाओं का समन्वय करती है।

महिलाओं के लिए सर्वोत्तम संस्था 2026 के रूप में ट्राइडेंट समूह सम्मानित

चंडीगढ़। ट्राइडेंट समूह को ईटी एज द्वारा ह्लमहिलाओं के लिए सर्वोत्तम संस्था 2026ह्व के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए समावेशी, सहयोगपूर्ण और सशक्त वातावरण विकसित करने की दिशा में समूह के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है। इस अवसर पर ट्राइडेंट समूह की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी पूजा बी. लूथरा ने कहा, ट्राइडेंट में महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी सोच, कार्यप्रणाली और विकास का अभिन्न हिस्सा है। हम ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां महिलाएं सम्मानित महसूस करें, उन्हें पूरा सहयोग मिले और वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह सम्मान हमारे इस विश्वास को और मजबूत करता है कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो संस्था भी अधिक सुदृढ़ बनती है। इस दिशा में समूह ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। श्रीजना, अस्मिता अवकाश और शगुन/आशीर्वाद जैसे कार्यक्रमों के साथ हस्तकला पहल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मातृत्व लाभ, लचीले कार्य विकल्प, स्वास्थ्य एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम तथा नेतृत्व विकास की व्यवस्थाएं भी महिलाओं को प्रदान की जा रही हैं।

मोहाली की 11 वर्षीय उभरती घुड़सवार प्रतिभा समायरा भांबरा ने दिल्ली हॉर्स शो 2026 में कांस्य पदक जीता

चंडीगढ़। मोहाली की 11 वर्षीय घुड़सवार प्रतिभा समायरा भांबरा ने अपनी शानदार प्रतिभा और आत्मविश्वास से सभी का दिल जीतते हुए दिल्ली हॉर्स शो 2026 में प्रतिष्ठित कांस्य पदक हासिल किया। राइजिंग स्टार ड्रेसेज इवेंट में प्रतिस्पर्धा करते हुए समायरा ने टीम वर्ग में भारत के 28 बेहतरीन युवा राइडर्स के बीच शानदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन में सटीकता, संतुलन और अटूट एकाग्रता साफ झलक रही थी, जिसने उनकी टीम को कांस्य पदक दिलाया और निर्णायकों व दर्शकों दोनों को प्रभावित किया। यह प्रतियोगिता घुड़सवारी कैलेंडर की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है, जिसमें देशभर से शीर्ष प्रतिभाओं ने भाग लिया, ऐसे में समायरा का पोडियम तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। समायरा की यह यात्रा उनके समर्पण और खेल के प्रति जुनून को दर्शाती है। चंडीगढ़ हॉर्स राइडर्स सोसाइटी में विशेषज्ञ मार्गदर्शन के तहत कठोर प्रशिक्षण लेते हुए वह लगातार अपने साथियों और प्रशिक्षकों को प्रेरित कर रही हैं। समायरा ने गर्व के साथ कहा कि यह पदक मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है और मुझे आगे और ऊंचा लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करता है।

हमदर्द लैबोरेटरीज ने होलीस्टिक हीलिंग अभियान की शुरूआत की

चंडीगढ़। भारत की प्रमुख और सबसे भरोसेमंद स्वास्थ्य और वेलनेस कंपनियों में से एक, हमदर्द लैबोरेटरीज ने वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 के अवसर पर पूरे देश में होलीस्टिक हीलिंग अभियान की शुरूआत की है, जो सुलभ, समग्र और समुदाय-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दोबारा रेखांकित करता है। इस अभियान के माध्यम से, हमदर्द लैबोरेटरीज का उद्देश्य निवारक वेलनेस और समग्र देखभाल को बढ़ावा देना है, जिसमें शोध, शिक्षा और समुदाय सहभागिता को मिलाया गया है। होलीस्टिक हीलिंग का विचार बीमारी के मूल कारणों को संबोधित करने और शरीर, मन और पर्यावरण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने पर केंद्रित है। भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियां और जीवनशैली से जुड़े रोग जैसे गैर-संक्रामक रोग (ठउउ२) एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गए हैं, जो लगभग 58.7 लाख मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार बताया गया है। ऐसे में, होलीस्टिक हीलिंग निवारण, जल्दी हस्तक्षेप और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

टैफे ने टैफे जेफार्म का उद्घाटन किया

चंडीगढ़। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने भवानी मंडी में अपने अनुकूली अनुसंधान केंद्र, टैफे जेफार्म राजस्थान का उद्घाटन किया जो टिकाऊ कृषि पद्धतियों को साझा करके कृषि उत्पादकता और किसानों की समृद्धि को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। कार्यक्रम की शुरूआत में श्री टी.आर. केशवन, ग्रुप प्रेसिडेंट - कॉर्पोरेट रिलेशन एंड अलायन्सेज, ने एक विशेष संबोधन प्रस्तुत किया। टैफे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संदीप सिन्हा ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर, टैफे की वाइस चेयरमैन डॉ. लक्ष्मी वेणु ने कहा हमारा मानना है कि क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संधारणीयता अपनाकर ही भारतीय कृषि प्रगति को गति मिल सकती है। जेफार्म राजस्थान का उद्घाटन इसी विश्वास का प्रतिबिंब है, साथ ही हम अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से किसानों के विकास में उनके साझेदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह केंद्र व्यावहारिक शिक्षण के अवसर प्रदान करता हैकृजहाँ किसान प्रत्यक्ष कृषि निदर्शनों, फसल-विशिष्ट अनुप्रयोगों और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समाधानों को देख, अनुभव और अपना पाएँगे। जेफार्म राजस्थान, एक प्रमुख केंद्र के रूप में, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने और राजस्थान तथा उत्तर भारत में किसानों तक इसके लाभ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नवजोत कौर सिद्धू ने नया राजनीतिक दल बनाया, नाम है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी

चंडीगढ़। पूर्व क्रिकेटर एवं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया। नवजोत कौर सिद्धू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के गठन का ऐलान किया। नवजोत कौर के अहम फैसले के दौरान नवजोत सिद्धू उनके साथ नहीं थे। वह इन दिनों क्रिकेट मैच की कमेंट्री में व्यवस्त हैं। डॉ.नवजोत कौर सिद्धू पंजाब में मुख्य संसदीय सचिव रह चुकी हैं। वह अपने पति के साथ कांग्रेस में भी सक्रिय रही हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी पार्टी का ऐलान बगैर किसी शोर-शराबे के किया। सोमवार देररात एक्स के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था, वह अब सामने है। हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है। हम बस अपना जीवन अपने देश को समर्पित करना चाहते हैं, और लोगों को वह सब लौटाना चाहते हैं जिसके वे सचमुच हकदार हैं और जिसकी वे हमसे उम्मीद करते हैं। यह एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जिसने कुछ ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ ला दिया है, जिनके पास हर राज्य में काम करने की क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प है। उनका साझा लक्ष्य है—न्याय और शांति प्रदान करना, और प्रेम के माध्यम से 'उच्च चेतना' की ऊर्जा के साथ काम करते हुए, ठीक वही कर दिखाना जो 'वाहेगुरु जी' हमसे चाहते हैं। हम पंजाब को उसकी खोई हुई पुरानी शान—एक स्वर्ण राज्य होने का गौरव—वापस दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा राज्य जहां लोग प्रेम, मिल-बांटकर रहने, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार और आजादी की शक्ति को पहचानते हों। जहां लोग बिना किसी बाहरी दखल के, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य से काम करते हुए अपने लक्ष्यों, मूल्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त करते हों। यह पंजाब के लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होगी।

पंजाब का गौरव: महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के कैडेट जसनूर सिंह सी.डी.एस. मेरिट सूची में पूरे भारत में अव्वल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

रक्षा बलों की तैयारी संबंधी शिक्षा में पंजाब के बढ़ते दबदबे की शानदार तस्वीर पेश करते हुए महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस संस्थान के 10वें कोर्स के कैडेट जसनूर सिंह ने कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज (सी.डी.एस.) एयर फोर्स सूची में ऑल इंडिया रैंक में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

Cadet Jasnoor Singh,
1st Rank CDS (Air Force)

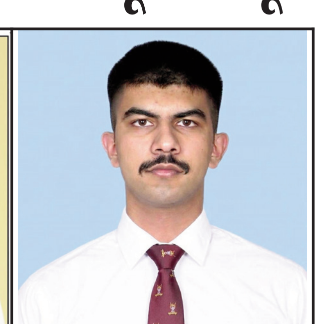

Cadet Sukhraj Singh Heera,
4th Rank CDS (Army)

इंस्टीट्यूट के एक और कैडेट ने पांचवीं बार हासिल किया ऑल-इंडिया टॉप रैंक

पठानकोट के एक व्यवसायी के पुत्र जसनूर सिंह अब प्री-फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए हैदराबाद में एयर फोर्स अकादमी जाएंगे। जसनूर की इस उपलब्धि के साथ संस्थान ने देश भर में पांचवीं बार शीर्ष रैंक प्राप्त करने में सफलता हासिल की है और पिछले दो वर्षों में संस्थान का यह तीसरा सम्मान है, जो मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इसके अलावा रोपड़ के कैडेट सुखराज सिंह हीरा ने चौथा ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया है और सुखराज अब जून 2026 में शुरू होने वाले 161वें कोर्स के लिए इंडियन मिलिट्री अकादमी (आईएमए), देहरादून में शामिल होंगे।

पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इन दोनों कैडेटों को दिल से बधाई देते हुए कहा, यह भारत के रक्षा बलों के भविष्य के अधिकारियों बनने के लिए उनका सफर शुरू होने जा रहा है। मैं उन्हें पूर्ण समर्पण और गंभीरता के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब को इन होनहार युवाओं की उपलब्धि पर सच्चे में गर्व है।

संस्थान के डायरेक्टर मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अजय एच. चौहान, वी.एस.एम. ने कैडेट जसनूर और सुखराज को संस्थान तथा पंजाब का गौरव बढ़ाने के लिए बधाई दी और कहा, हम एनडीए-156 कोर्स की मेरिट सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हमें एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।

पुलिस टीमों ने 89 व्यक्तियों के खिलाफ की एहतियाती कार्रवाई, 58 को पूछताछ के बाद किया रिहा

गैंगस्टरों ते वार का 77वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 501 स्थानों पर छापेमारी; 202 गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेशों पर शुरू की गई निर्णायक गैंगस्टरों ते वार मुहिम के 77वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 501 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक व्यापक मुहिम है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जी टी एफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

77वें दिन की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 202 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 19,450 हो गई है।

इसके अतिरिक्त 89 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 58 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। इस दौरान पुलिस ने 10 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

जनता एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकती है तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकती है।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से दे सकते हैं जानकारी

युद्ध नशों विरुद्ध के 402वें दिन 5.8 किलो हेरोइन सहित 112 नशा तस्कर गिरफ्तार

इसी दौरान पंजाब पुलिस ने युद्ध नशों विरुद्ध अभियान को 402वें दिन भी जारी रखते हुए 112 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5.8 किलोग्राम हेरोइन, 587 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 19,050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इस प्रकार 402 दिनों में कुल 57,519 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने आज 73 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित भी किया, जिससे समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में कंडक्टर गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपनी मुहिम के तहत पी.आर.टी.सी. डिपो बठिंडा में तैनात कंडक्टर नरेंद्र सिंह उर्फ लाडी को 20,000 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को तहसील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा के निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता पीआरटीसी डिपो बठिंडा में ड्राइवर के रूप में कार्यरत है और वह अपना बस रूट बदलवाना चाहता था। इस संबंध में आरोपी केवल कृष्ण, फिटर इंचार्ज बस स्टैंड गोनियाना और कंडक्टर नरेंद्र सिंह उर्फ लाडी ने बस रूट बदलने के बदले शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं देना चाहता था, जिसके चलते उसने विजिलेंस ब्यूरो रेंज बठिंडा से संपर्क किया। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी कंडक्टर को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। इस संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना बठिंडा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सह-आरोपी फिटर केवल कृष्ण को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की आगे की जांच जारी है।

ईरान में सवेरा होने से पहले तेहरान और आसपास के हिस्सों पर हमला

तेहरान के आसमान में धमाकों की गूंज, रणनीतिक ठिकानों को बनाया निशाना

डोनाल्ड ट्रंप की सख्त समय सीमा: 'होर्मुज खोलो वरना पाषाण युग के लिए तैयार रह'

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान/तेल अवीव/ वाशिंगटन

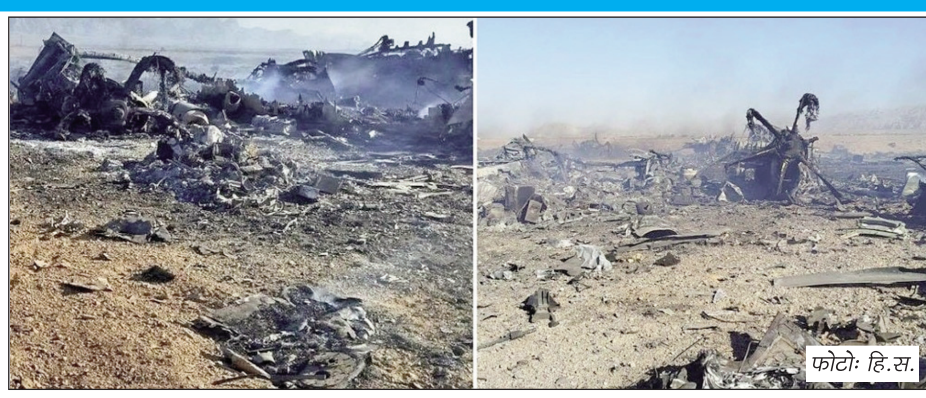
फोटोः हि.स.

अमेरिका-इजराइल का ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू किया एकीकृत सैन्य अभियान दिन गुजरने के साथ-साथ डरावना होता जा रहा है। ईरान ने दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। यह युद्ध आज सुबह 39वें दिन में प्रवेश कर गया। इजराइल ने मंगलवार को सवेरा होने से पहले ईरान के कई शहरों पर भीषण हमले किए हैं। इस बीच जैसे-जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज को खोलने की समय सीमा नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे मध्य पूर्व में भय का वातावरण घर कर रहा है। ईरान कह चुका है कि उसे ट्रंप की चेतावनी की परवाह नहीं। अगर उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को ट्रंप ने निशाना बनाया तो वह भी वैसा ही जवाब देगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल, सीबीएस न्यूज और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने मंगलवार को स्थानीय समयानुसार तड़के बताया कि उसने राजधानी तेहरान और ईरान के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल की सेना ने अपने लक्ष्यों की सूची जारी की। इनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई ठिकाने, मिसाइल साइटें और पेट्रो केमिकल संयंत्र शामिल थे। आईडीएफ ने दावा किया कि इन्हीं लक्ष्यों पर मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तेहरान के अलावा राजधानी के पश्चिमी उपनगर करज में जोरदार धमाके हुए हैं। एक जोरदार धमाका मेहराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास हुआ है। इस हवाई अड्डे के पास शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब हमला न हुआ हो। उधर, सोमवार को पूरे दिन ईरान भर में हुए अमेरिका-इजराइल के हमलों में कम से कम 34 लोग मारे गए, जबकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने खाड़ी देशों में मौजूद अहम ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार की समय सीमा तक होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से नहीं खोला गया तो उसके कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के बिजली संयंत्र और पुलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप की चेतावनी के बीच व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक बयान में चेतावनी दी कि अगर ईरान बातचीत में गंभीरता से शामिल होने में नाकाम रहता है, तो कल रात उसे पाषाण युग में भेज दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की मुख्य उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम में उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेशमंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर शामिल हैं। इस टीम ने बातचीत शुरू करने की पहल की है।

ट्रम्प का बड़ा दावा-ईरान में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन एक रात में तबाही की चेतावनी

एजेंसी (हि.स.)
वॉशिंगटन

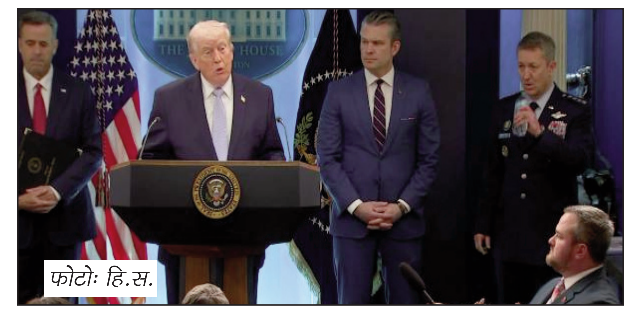
फोटोः हि.स.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने दुश्मन के इलाके में फंसे अपने एक पायलट को बचाने के लिएअब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रम्प ने बताया कि इस अभियान में करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया और 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयरस्पेस में भेजे गए। उनके मुताबिक, पायलट ईरान के क्षेत्र में गिरा था और बेहद खतरनाक हालात में उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया।

ट्रम्प ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद सेना ने साहस दिखाते हुए मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने अमेरिकी सैनिकों केशौर्य और साहस की सराहना की। हालांकि, अपने बयान में ट्रम्प ने सख्त रुख भी अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकासिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है और ऐसी कार्रवाई कभी भी संभव है। इस बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ सकती है। ट्रम्प ने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी विमान को खुद ही नष्ट (सेल्फ-डिस्ट्रक्ट) करना पड़ा, ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे। उन्होंने दावा किया कि मिशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक हो गई थी, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है। इस दौरान उन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए) की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि एजेंसी ने पूरे अभियान में अहम योगदान दिया।

ट्रंप ने सहयोगी देशों पर साधा निशाना, कहा-युद्ध में किसी ने मदद नहीं की

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर अपने कई सहयोगी देशों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों ने इस संघर्ष के दौरान कोई मदद नहीं की। व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा,जापान ने हमारी मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने मदद नहीं की, दक्षिण कोरिया ने मदद नहीं की, और फिर नाटो उसने भी कोई मदद नहीं की। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका इन देशों की सुरक्षा के लिए बड़ी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि जापान में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो उसे किम जोंग उन के नेतृत्व वाले नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं साउथ कोरिया में भी लगभग 45,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। हालांकि, ट्रंप ने कुछ खाड़ी देशों की सराहना भी की। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमिरात, बहरीन और कुवैत कोबेहतरीन सहयोगी बताते हुए कहा कि इन देशों ने हालात को देखते हुए सक्रिय भूमिका निभाई है। ट्रंप के इन बयानों से अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं, जिससे वैश्विक कूटनीति पर असर पड़ सकता है।

ट्रंप की धमकी से ईरान घबराया, युवाओं से बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव शृंखला बनाने का आह्वान

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान/वाशिंगटन

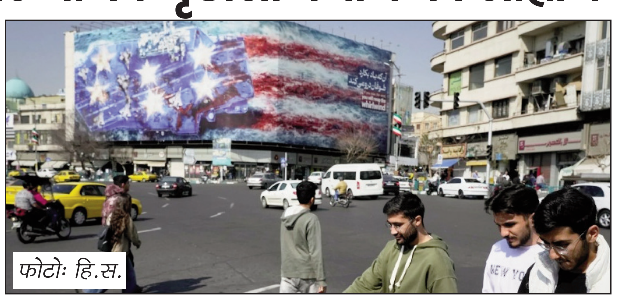
फोटोः हि.स.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मंगलवार तक न खोलने पर दी गई हमले की चेतावनी से ईरान घबरा गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एक ही रात (मंगलवार रात) में पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। ईरान के युवा और खेल मामलों के उपमंत्री अलीरेजा रहीमी ने ट्रंप की धमकी के मद्देनजर देश के युवाओं से बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव शृंखला बनाने का आान किया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अलीरेजा रहीमी ने ट्रंप की धमकी के बाद यह अपील की है। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर बमबारी करेगा। रहीमी ने एक्स पर लिखा, मैं सभी युवाओं, सांस्कृतिक और कला जगत की हस्तियों, खिलाड़ियों और चैंपियनों को राष्ट्रीय अभियान 'ईरानी युवाओं की मानव शृंखला- एक उज्ज्वल भविष्य के लिए' में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने लिखा मंगलवार दोपहर दो बजे देशभर के बिजली संयंत्रों के पास हम सभी अपनी-अपनी मान्यताओं और विचारों के साथ एक-दूसरे का हाथ थामकर खड़े होंगे और यह संदेश देंगे कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर हमला करना एक 'युद्ध अपराध' है। उल्लेखनीय है कि सप्ताहांत ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास किसी समझौते पर पहुंचने के लिए मंगलवार रात आठ बजे (पूर्वी समय) तक का समय है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद मंगलवार को हो सकता है। उन्होंने कहा यह एक नाजुक दौर है। और यह सब ईरान के कदमों पर निर्भर करता है। ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर हमला करने की धमकी दोहराते हुए दावा किया कि अगर इससे ईरानी लोगों की आजादी सुनिश्चित होती है तो वह तकलीफ उठाने को भी तैयार होंगे। उधर, तेहरान ने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों के नतीजे इस क्षेत्र से भी आगे तक जाएंगे।

नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल मॉरीशस के दौरे पर जाएंगे, भारतीय विदेशमंत्री से भी होगी मुलाकात

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल मॉरीशस की यात्रा पर जाने वाले हैं। वह 10 अप्रैल को मॉरीशस में इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन (इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस) में भाग लेने के लिए गुरुवार को प्रस्थान करेंगे। विदेशमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा होगा।

यह सम्मेलन मॉरीशस सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य विषयहिंद महासागर के सुशासन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी रखा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री ने जानकारी दी कि मंत्री खनाल सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरीशस जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय विदेशमंत्री एस. जयशंकर सहित विभिन्न देशों के विदेशमंत्री और उच्चस्तरीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नेपाल के विदेशमंत्री खनाल सम्मेलन के दौरान अपने भारतीय समकक्ष डॉ. एस. जयशंकर के साथ साइडलाइनबैठक भी करेंगे। इसके अलावा अन्य देशों के नेताओं के साथ भी उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें तय हैं। सम्मेलन में खलिलुर रहमान (बांग्लादेश), विजिथा हेराथ (श्रीलंका), डीएन ढुंगेल (भूटान), बद्र हमाद अल बुसैदी (ओमान) और बैरी फाउर (सेशेल्स) समेत कई देशों के विदेश मंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा कंबोडिया, मिस्र, मेडागास्कर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम के अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। इंडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें नेपाल की नियमित भागीदारी रही है। पिछले वर्ष फरवरी में मस्कट में आयोजित आठवें सम्मेलन में तत्कालीन विदेशमंत्री आरजु राणा देउवा ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना, समुद्री व्यापार को सुदृढ़ करना, आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करना है।

इंडिया फाउंडेशन के अनुसार, पिछले आठ वर्षों में यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए साझा मुद्दों पर विचार-विमर्श का एक प्रमुख मंच बन चुका है।

संक्षिप्त-समाचार

दिल्ली-एनसीआर में बरसा पानी, मौसम हुआ सुहाना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में आज सुबह बरसात होने से मौसम सुहावना हो गया। कुछ स्थानों पर तो अभी भी बूंदाबांदी हो रही रही है। आसमान पर बादलों का डेरा है। हवा में ठंडक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली-एनसीआर में आज और कल पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश और तेज हवाओं का पूवार्नुमान जता चुका है। दिल्ली-एनसीआर प्रमुख महानगरीय क्षेत्र है। इसमें दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पड़ोसी जिले शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम में आए इस बदलाव के लिए कारक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को बताया है। विभाग ने आज और कल हलकी बरसात के बीच 30 से 50 किलीमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद जताई है। विभाग ने कहा कि तापमान में भी तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इस दौरान मौसम खुशगवार बना रहेगा।

नेपाल सरकार ने राजनीतिक आधार पर नियुक्ति किए गए भारत सहित छह राजदूतों को वापस बुलाया

काठमांडू। नेपाल सरकार ने भारत सहित 6 देशों में राजनीतिक आधार पर नियुक्त राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने इस निर्णय को अनुमोदन किया गया। यह कदम सरकार परिवर्तन के बाद पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में नियुक्त राजदूतों को वापस बुलाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उठाया गया है। वापस बुलाए गए राजदूतों में डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा (भारत में नेपाल के राजदूत), चित्रलेखा यादव (ऑस्ट्रेलिया में राजदूत) और डॉ. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया में राजदूत) शामिल हैं। इसी तरह डॉ. पूर्ण बहादुर नेपाली (श्रीलंका), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) और कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रीका) को भी वापस बुलाया गया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वापस बुलाए गए राजदूतों को नेपाल लौटने के लिए एक महीने की समय सीमा दी गई है। जिससे उनका शेष कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। सरकार आने वाले दिनों में खाली होने वाले कूटनीतिक पदों पर नए राजदूतों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। नेपाल में सरकार द्वारा राजदूत नियुक्ति होने के बाद संसद की सुनवाई समिति के सामने पेश होना होता है जहां अनुमोदन के बाद ही उनका एग्रीमो संबंधित देशों में भेजा जाता है।

असहाय विधवा को राहत : बैंक ऋण निस्तारण शिक्षा व भरण-पोषण में प्रशासन बना सहारा

देहरादून। जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए असहाय विधवा क्षमा परवीन को बड़ी राहत प्रदान की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निदेर्शों पर संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर उनका बकाया ऋण वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के माध्यम से निस्तारित कराया गया और बैंक से एनओसी और नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी कराया गया। सेटलमेंट के उपरांत शेष 33 हजार रुपये की धनराशि भी जिला प्रशासन द्वारा जमा कराई गई। क्षमा परवीन ने 28 मार्च 2026 को जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के विवाह के लिए डीसीबी बैंक से सवा लाख रुपये का ऋण लिया था। उसी वर्ष उनके पति का निधन हो गया, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया। इसके बाद वर्ष 2020 में कोविड-19 के दौरान उनकी बड़ी विवाहित बेटी की भी मृत्यु हो गई। लगातार विपरीत परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह शेष ऋण चुकाने में असमर्थ रहीं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बैंक से समन्वय स्थापित कर ऋण को ओटीएस के तहत समाप्त कराया और एनओसी जारी कराई। वर्तमान में क्षमा परवीन पर तीन अविवाहित बेटियों, एक पुत्र तथा पांच वर्षीय नातिन के भरण-पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान की। छोटी बेटी फैजा की पढ़ाई ह्लनंदा-सुनंदा योजनाह्व के तहत पुनः शुरू कराई गई और 27 हजार रुपये की फीस जमा कराई गई। वहीं, नातिन आयरा को आरटीई के तहत निकटवर्ती निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। दाखिले में आ रही आय प्रमाण पत्र की बाधा को दूर करते हुए मौके पर ही प्रमाण पत्र जारी कराया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जरूरतमंद एवं असहाय नागरिकों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर सहायता सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रकरणों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

मप्र के उज्जैन में भरभराकर गिरा तीन मंजिला मकान, लोगों की सूझबूझ से बचीं कई जानें

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सोमवार की रात गेबी हनुमान क्षेत्र में एक तीन मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय रहवासियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और कई लोगों की जान बच गई। मंगलवार को घटना एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तीन मंजिला मकान को गिरते हुए स्पष्ट देखा सकता है। यह घटना महाकाल मंदिर जाने वाले प्रमुख मार्ग पर हुई। जिस जगह मकान गिरा, वहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोपाल मंदिर, शिप्रा नदी और महाकाल मंदिर की ओर जाते हैं। सोमवार शाम से ही मकान एक तरफ झुकना शुरू हो गया था, यह देख लोगों ने रास्ता बंद करा दिया। रात करीब सवा 7 बजे के मकान गिर गया। समय रहते रहवासियों ने आवाजाही रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अगर यातायात नहीं रोका जाता तो कई लोग इस हादसे के शिकार हो सकते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम करीब 6 बजे से मकान की स्थिति खराब होने लगी थी। उन्हें खतरे का अंदेशा हुआ और उन्होंने तुरंत एहतियात के तौर पर सड़क खाली करा दी। घटना की सूचना मिलते ही 2 सीएसपी सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और रोड को ब्लॉक कर आवाजाही पर रोक लगा दी। दुर्घटनास्थल पर पुलिसबल भी तैनात किया गया है। दरअसल, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान ढाबा रोड में नगर निगम द्वारा नाला खुलाई का काम किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा करीब 1 महीने से 10 फीट गहरा नाला खोदकर छोड़ दिया गया है। इसमें पानी भर गया है जिससे आसपास बने कई मकानों की नींव कमजोर हो गई है। मकान मालिक मनोज भावसार और अली अजगर सहित रहवासियों का आरोप है कि पोकलेन मशीन से चल रही तोड़फोड़ के चलते हादसा हुआ। साथ ही एक महीने से नींव में पानी भरने की शिकायत भी की जा रही थी। जीवाजीगंज सीएसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि गेबी हनुमान मंदिर के पास मकान गिरने की सूचना मिली थी। तुंरत मौके पर कोतवाली और जीवाजीगंज पुलिस फोर्स पहुंची।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

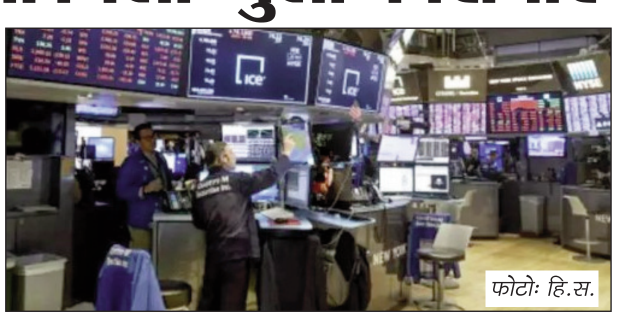
फोटोः हि.स.

ग्लोबल मार्केट से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में छुट्टी होने की वजह से पिछले सत्र के दौरान कोई कारोबार नहीं हुआ। वहीं एशियाई बाजार में आज मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

पश्चिम एशिया में जारी जंग को रोकने के लिए सोमवार को आए दो शांति प्रस्तावों की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा। इस उत्साह के कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 165.21 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की मजबूती के साथ 46,669.88 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,611.83 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा नैस्डेक 117.16 अंक यानी 0.54 प्रतिशत उछल कर 21,996.34 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर, ईरान द्वारा युद्ध रोकने के दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिए जाने की वजह से आज डाउ जॉन्स फ्यूचर्स 0.15 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 46,601.01 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

एशियाई बाजार में आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के नौ बाजार में से पांच के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि तीन सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में छुट्टी होने की वजह से हैंग सेंग इंडेक्स में आज कोई उतार-चढ़ाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच समाचार चैनलों की टीआरपी पर रोक को चार सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टीवी समाचार चैनलों की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी को और चार सप्ताह के लिए रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम संकट के समय फैलने वाली अटकलों और सनसनीखेज खबरों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल(बीएआरसी) को यह निर्देश इजराइल-ईरान संघर्ष के दौरान गलत और काल्पनिक खबरों के प्रसारण के बाद दिया है, ताकि जनता में दहशत न फैले। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि कुछ समाचार चैनल अनावश्यक रूप से सनसनीखेज तरीके से युद्ध की स्थिति को प्रसारित कर रहे हैं। इस तरह की सामग्री से आम जनता में भ्रम और भय का माहौल बन सकता है। विशेषकर प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के परिजनों में चिंता और असुरक्षा की भावना बढ़ने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चार सप्ताह के लिए टीवी समाचार चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है । इस दौरान चैनलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन सामान्य प्रक्रिया के तहत नहीं किया जाएगा।

रिजर्व बैंक गवर्नर आज सुबह 10 बजे एमपीसी समीक्षा बैठक के नतीजों की करेंगे घोषणा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक दूसरे दिन भी चल रही है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सोमवार को इस बैठक की शुरूआत की। इस बैठक के फैसले की घोषणा बुधवार को रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे करेंगे।

आरबीआई ने मंगलवार को ह्यएक्सह्न पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि मौद्रिक नीति की घोषणा 8 अप्रैल, 2026 को निर्धारित है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को सुबह 10 बजे बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में चल रही यह बैठक एक मुश्किल समय में हो रही है, क्योंकि वैश्विक तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों ने केंद्रीय बैंक के काम को और भी जटिल बना दिया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच आरबीआई की चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली तीन दिवसीय समीक्षा बैठक चल रही है, यह समीक्षा बैठक 8 अप्रैल तक चलेगी। अर्थशास्त्रियों ने रेपो रेट 5.25 फीसदी पर बने रहने की संभावना जताई है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मुद्रा संबंधी दबावों के बीच आर्थिक परिदृश्य का आकलन करने के लिए आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा बैठक में केंद्रीय बैंक इस बार भी रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर यथावत बनाए रखेगा। इस समीक्षा बैठक में नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट और महंगाई पर फैसला लिया जाएगा।

नक्सली जहां सरकार विरोधी शिक्षा देते थे, वहां खोले जाएंगे 22 स्कूल

एजेंसी (हि.स.)
सुकमा

बस्तर के सुदूर वनांचलों के जिन गांवों में कभी बच्चों को जनताना स्कूलों के जरिए माओवादी विचारधारा की शिक्षा दी जाती थी, वहां अब भारतीय संविधान और औपचारिक शिक्षा की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में शिक्षा विभाग ने 22 नए स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा है। यह उन बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जिन्होंने अब तक स्कूल की दहलीज नहीं देखी है।

गौरतलब है कि बीजापुर और सुकमा जिले के कई नक्सल प्रभावित गांव वर्षों तक पहुंच से बाहर रहे, यहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों में 10 साल तक के बच्चों को अब नर्सरी में दाखिला देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं। कोंटा ब्लॉक की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही है। हिड़मा के गांव पूवर्ती में सीआरपीएफ द्वारा गुरुकुल शुरू किए जाने के बाद बदलाव की शुरूआत हुई। करीब 20 साल बाद यहां बच्चों को पहली बार बताया गया कि स्कूल क्या होता है, ब्लैकबोर्ड कैसे काम करता है, और पढ़ाई कैसे की जाती है। आज पूवर्ती गुरुकुल में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग के स्कूल में भी 20 से अधिक बच्चों ने प्रवेश लिया है। टेकलागुड़ा सहित अन्य गांवों में भी कैंप खुलने के बाद स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस बदलाव की बयार अब नक्सलियों के मिलिट्री दलम के कमांडर रहे आत्मसमर्पित नक्सली बारसा देवा के गांव तक पहुंच रही है। सुकमा जिले के ओयोपारा जैसे गांव, जहां अब तक केवल जनताना स्कूल संचालित होते थे, वहां शिक्षा विभाग की टीम बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार संपर्क कर रही है।

शिक्षा

आर.टी.ई. प्रतिपूर्ति राशि दूसरे राज्यों से बेहतर

साढ़े तीन लाख से अधिक बच्चे ले रहे लाभ

छत्तीसगढ़ में आर.टी.ई. के तहत प्रवेश नहीं देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द

एजेंसी (हि.स.)
रायपुर

फोटोः हि.स.

छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले राज्य सरकार प्रति बच्चा व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर या उनके समकक्ष है। प्रदेश में वर्ष 2011-12 से ही कक्षा 1 से 5 तक 7000 रूपए और कक्षा 6 से 8 तक 11 हजार 400 रूपए वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित है। तुलनात्मक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में 4,419 रूपए बिहार में 6,569 रूपए, झारखंड में 5,100 रूपए और उत्तर प्रदेश में 5,400 रूपए वार्षिक दिए जाते हैं। यद्यपि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, किंतु समग्र मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि संतुलित और उचित है। वर्तमान में राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. के माध्यम से लगभग 3,63,515 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस वर्ष भी कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। चूंकि सभी निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही मान्यता दी गई है, अतः यह उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें। यदि कोई निजी विद्यालय आर.टी.ई. के तहत प्रवेश देने से इंकार करता है या प्रक्रिया में व्यवधान डालता है, तो राज्य शासन उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान शामिल है। शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस संबंध में फैलाई जा रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक तथ्यों पर ही विश्वास करें।

फीफा वर्ल्ड कप 2026: सोफी स्टेडियम के कर्मचारियों की 'हड़ताल' की चेतावनी

इमिग्रेशन एजेंसी की भूमिका पर विवाद और सुरक्षा की मांग

एजेंसी (हि.स.)
लॉस एंजेलिस

फोटोः हि.स.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले लॉस एंजेलिस स्थित सोफी स्टेडियम में काम करने वाले करीब 2,000 फूड सर्विस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन ने बड़ा कदम उठाया है। यूनियन ने मांग की है कि टूर्नामेंट के दौरान अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) को वर्ल्ड कप संचालन से दूर रखा जाए, अन्यथा कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं।

यूनाइट हियर लोकल 11, जो इस स्टेडियम में कुक, सर्वर और बारटेंडर का प्रतिनिधित्व करता है, ने सोमवार को कहा कि वर्ल्ड कप नजदीक आने के बावजूद कर्मचारियों के पास अब तक कोई श्रम अनुबंध नहीं है। यूनियन ने फीफा और स्टेडियम के मालिक क्रोंके स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें आईसीई और बॉर्डर पेट्रोल की किसी भी भूमिका को लेकर सार्वजनिक आश्वासन, यूनियन कर्मचारियों की नौकरी और कार्य परिस्थितियों की सुरक्षा, तथा हॉस्पिटैलिटी कर्मचारियों के लिए किफायती आवास का समर्थन शामिल है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के कार्यवाहक निदेशक टॉड लायंस ने हाल ही में कहा था कि वर्ल्ड कप में आईसीई 'महत्वपूर्ण भूमिका' निभाएगा। इस बयान पर यूनियन ने चिंता जताते हुए कहा कि इससे लॉस एंजेलिस में कामगारों और दर्शकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इस मुद्दे पर फीफा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि सोफी स्टेडियम प्रबंधन ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

यूनियन ने यह भी मांग की है कि टूर्नामेंट के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का उपयोग कर कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त न की जाएं। इसके अलावा यूनियन ने लॉस एंजेलिस, विशेषकर इंग्लवुड क्षेत्र में बढ़ती आवास लागत को लेकर भी चिंता जताई है और वर्कफोर्स हाउसिंग फंड, शॉर्ट-टर्म रेंटल पर नियंत्रण तथा किफायती आवास और प्रवासी परिवारों की सुरक्षा के लिए कर उपायों की मांग की है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले कोलंबिया को राहतः जेम्स रोड्रिगेज ट्रेनिंग पर लौटे

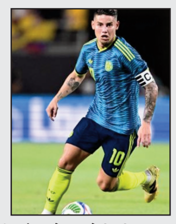

लॉस एंजेलिस/मिनेसोटा। कोलंबिया के स्टार फुटबॉलर जेम्स रोड्रिगेज से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। गंभीर डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह अब अपने क्लब मिनेसोटा यूनाइटेड के साथ ट्रेनिंग पर लौट आए हैं। 34 वर्षीय रोड्रिगेज पिछले सप्ताह तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उन्हें 29 मार्च को फ्रांस के खिलाफ खेले गए मैच के बाद तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां जांच में गंभीर डिहाइड्रेशन की पुष्टि हुई। शुरुआत में अमेरिकी मीडिया में उनकी स्थिति को लेकर गंभीर बीमारी (रैबडोमायोलिसिस) की आशंका जताई गई थी, लेकिन मिनेसोटा यूनाइटेड ने इन खबरों का खंडन किया। क्लब ने स्पष्ट किया कि मेडिकल जांच में ऐसी किसी गंभीर बीमारी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। क्लब के अनुसार, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रोड्रिगेज घर पर आराम कर रहे थे और अब उन्होंने 'नियंत्रित ट्रेनिंग सत्र' के साथ मैदान पर वापसी की है। उनकी पूर्ण रूप से टीम ट्रेनिंग में वापसी क्लब के मेडिकल स्टाफ की निगरानी और उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार होगी। गौरतलब है कि जेम्स रोड्रिगेज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कोलंबिया टीम के अहम खिलाड़ी हैं।

खालसा, किरोड़ी मल, स्टनर अकादमी और रामजस ने जीत के साथ की शुरूआत

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पीएसपीबी बाबा दीप सिंह बास्केटबॉल टूर्नामेंट

पांचवें पीएसपीबी बाबा दीप सिंह बास्केटबॉल (पुरुष एवं महिला) टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार को रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ, जिसमें मेजबान श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, किरोड़ी मल कॉलेज, स्टनर अकादमी और रामजस कॉलेज ने अपने-अपने शुरूआती मैच जीतकर जीत से शुरूआत की। पुरुष वर्ग के मुकाबले में मेजबान एसजीटीबी खालसा कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी को 77-42 से हराया। टीम की जीत में रूपेश भाटी का अहम योगदान रहा, जिन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

एक अन्य मुकाबले में किरोड़ी मल कॉलेज ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को 80-60 से पराजित किया। किरोड़ी मल कॉलेज के भाव्या को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' घोषित किया गया। वहीं, महिला वर्ग में स्टनर अकादमी ने आईपी कॉलेज पर 76-40 से एकतरफा जीत दर्ज की। इस मैच में शेरिल के शानदार खेल के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, एक अन्य मुकाबले में रामजस कॉलेज ने किरोड़ी मल कॉलेज को 40-28 से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरूआत की। इस मुकाबले में वेदा श्रीवास्तव को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

इससे पहले टूर्नामेंट का उद्घाटन पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (पीएसपीबी) के संयुक्त सचिव संदीप सरकारिया, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्राचार्य प्रो. गुरमोहिंदर सिंह तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान निदेशक डॉ. इंदरप्रीत कौर ने संयुक्त रूप से किया।

भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम रूस में खेलेगी तीन मैत्री मैच

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारत की अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम रूस के सोची में 11, 14 और 17 अप्रैल 2026 को मेजबान टीम के खिलाफ तीन मैत्री मैच खेलेगी। मुख्य कोच पामेला कोंटी ने इस दौरे के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सभी मुकाबले सोची के मात्सेस्टा फुटबॉल सेंटर में खेले जाएंगे और भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे। यंग टाइग्रेसेस, जो एएफसी अंडर-17 महिला एशियन कप चीन 2026 की तैयारियों में जुटी हैं, 6 अप्रैल की रात सोची पहुंची। पिछले महीने टीम ने यांगून का दौरा किया था, जहां उसने मेजबान टीम के खिलाफ दो मैत्री मैच खेले और दोनों में जीत दर्ज की (2-0 और 3-2)। इसके बाद टीम ने बेंगलुरु में अपना प्रशिक्षण शिविर जारी रखा। एशियन कप में, जो सूझोउ में खेला जाएगा, भारत को ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया (2 मई), जापान (5 मई) और लेबनान (8 मई) के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं।

रूस दौरे के लिए भारत अंडर-17 महिला टीम 23 सदस्यीय

गोलकीपरः मुन्नी, सूरजमुनी कुमारी, तम्फसाना देवी कोंजेंगबम **डिफेंडरः** एलेना देवी सारंगथेम, अलीशा लिंगदोह, दिव्यानी लिंडा, एलिजाबेथ लकड़ा, जॉयशिनी चानू हुइद्रोम, रितु बड़ाइक, तानिया देवी तोनंबम **मिडफील्डरः** अभिस्ता बसनेट, अल्वा देवी सेंजम, बोनिफिलिया शुल्लई, जूलन नोंगमैथेम, प्रीतिका बर्मन, रेडिमा देवी चिंगखामायुम, थंदामोनी बास्के **फॉरवर्डः** अनुश्का कुमारी, अन्विता रघुरामन, जॉय, ओलिविया चानू निंगथौजाम, पर्ल फर्नांडिस, वलैना फर्नांडिस **कोचिंग स्टाफ- मुख्य कोचः** पामेला कोंटी, **सहायक कोचः** विन्सेन्जो कोंटी, निवेथा रामदास, **गोलकीपिंग कोचः** मारियो अगियार, **स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचः** अमित यादव।

मैच कार्यक्रम

11 अप्रैलः रूस बनाम भारत (दोपहर 2:30 बजे)। **14 अप्रैलः** रूस बनाम भारत (दोपहर 2:30 बजे)। **17 अप्रैलः** रूस बनाम भारत (दोपहर 2:30 बजे)। **स्थानः** मात्सेस्टा फुटबॉल सेंटर, सोची।

पूर्व वाडा अध्यक्ष क्रेग रीडी का 84 वर्ष की आयु में निधन

नई दिल्ली। विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) के पूर्व अध्यक्ष क्रेग रीडी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने सोमवार को उनके निधन की पुष्टि की, हालांकि मौत के कारण का खुलासा नहीं किया गया है। क्रेग रीडी खेल प्रशासन में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे और उन्होंने ओलंपिक आंदोलन तथा डोपिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 2013 में वाडा के अध्यक्ष बने थे और अपने कार्यकाल के दौरान रूस के डोपिंग विवाद को लेकर उनके रुख ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। रीडी ने 2012 लंदन ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने की बोली में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने बैडमिंटन को 1992 बार्सिलोना ओलंपिक खेलों में शामिल कराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए ने रीडी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपना मार्गदर्शक, सलाहकार और करीबी मित्र बताया। उन्होंने कहा कि रीडी ओलंपिक खेलों के गहन ज्ञान और अनुभव के धनी थे, जिसे उन्होंने हमेशा साझा किया। रीडी का कार्यकाल 2016 रियो ओलंपिक से पहले रूस के राज्य प्रायोजित डोपिंग घोटाले के कारण काफी चुनौतीपूर्ण रहा। वाडा की ओर से रूस की पूरी टीम को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन आईओसी और उसके अध्यक्ष थॉमस बाक ने इसका विरोध किया।

अर्जेंटीना दौरे पर जाएगी भारतीय महिला हॉकी टीम

खेलेगी चार मैचों की सीरीज

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम इस महीने चार मैचों की सीरीज के लिए अर्जेंटीना दौरे पर जाएगी। यह सीरीज 13 से 17 अप्रैल के बीच ब्यूनस आयर्स स्थित सिनार्ड में खेली जाएगी। इस सीरीज में भारत अपने घरेलू मैदान पर मजबूत दक्षिण अमेरिकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगा, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। मैच 13, 14, 16 और 17 अप्रैल को खेले जाएंगे, जिनका समय स्थानीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे) रहेगा।

भारत और अर्जेंटीना के बीच पिछले कुछ वर्षों में कड़े मुकाबले देखने को मिले हैं, जिसमें पिछले साल जून में एफआईएच प्रो लीग 2024-25 के दौरान 2-2 से ड्रॉ मुकाबला भी शामिल है, जिसका फैसला शूटआउट से हुआ था। यह दौरा भारत के लिए उच्च स्तर की अंतरराष्ट्रीय टीम के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच अभ्यास का अवसर प्रदान करेगा और हॉकी इंडिया की रणनीतिक योजना के अनुरूप टीम को 2026 के एफआईएच हॉकी विश्व कप (बेल्जियम और नीदरलैंड) और इस साल होने वाले एशियाई खेलों से पहले लय हासिल करने में मदद करेगा। यह सीरीज भारत के लिए काफी अहम तैयारी साबित होगी, जिसमें टीम को चार तेज-तर्रार मैच खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही, कोचिंग स्टाफ को खिलाड़ियों के विभिन्न संयोजन और रणनीतियों को आजमाने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि टीम अपने कैलेंडर के महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रही है।

दौरे को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच श्योर्ड मारिन ने कहा, 'हम 24 खिलाड़ियों के दल के साथ अर्जेंटीना जा रहे हैं और यह एक सोचा-समझा फैसला है। इस दौरे का मकसद ज्यादा खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर प्रदर्शन का मौका देना है। अर्जेंटीना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है और वहां का माहौल हमें बताएगा कि हर खिलाड़ी किस स्तर पर खड़ा है। हम देखना चाहते हैं कि दबाव के समय कौन खिलाड़ी आगे आता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'इस टीम में जगह बनाने के लिए सबसे पहले एक टीम खिलाड़ी होना जरूरी है। व्यक्तिगत क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आप टीम के साथ तालमेल नहीं बैठा सकते और एक-दूसरे के लिए काम नहीं कर सकते, तो इस टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा।'

इंटेंस रोमांस के साथ 'चांद मेरा दिल' का टीजर रिलीज

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की आगामी फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टीजर जारी कर दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है। रिलीज से पहले ही यह फिल्म अपनी कहानी और स्टारकास्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई है। टीजर की शुरूआत अनन्या और लक्ष्य के रोमांटिक रिश्ते से होती है, जिसमें दोनों के बीच गहरा प्यार दिखाया गया है। बैकग्राउंड में प्यार में थोड़ा पागल तो होना ही पड़ता है जैसी लाइन कहानी की भावनात्मक टोन को सेट करती है। हालांकि, जल्द ही कहानी में एक मोड़ आता है और दोनों के रिश्ते में दूरियां और तड़प देखने को मिलती है, जो फिल्म को एक इंटेंस लव स्टोरी का रूप देता है। करण जौहर एक बार फिर प्यार, दर्द और जुनून से भरी कहानी के जरिए दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह फिल्म म्यूजिकल-रोमांटिक जॉनर में एक भावनात्मक सफर पेश करेगी। 'चांद मेरा दिल' 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'धुरंधर 2' के कमाई में आई गिरावट

रणवीर सिंह. कारोबारी दिनों में लौटते ही फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है। रिलीज के 19वें दिन यानी सोमवार को फिल्म ने 10 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम है।

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, 17वें दिन फिल्म ने 25.65 करोड़ रुपये और 18वें दिन 28.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके मुकाबले 19वें दिन आई गिरावट साफ नजर आती है। बावजूद इसके फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब 1,023.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन चुकी है।

वहीं, वैश्विक स्तर पर भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार बना हुआ है। 'धुरंधर 2' ने 19 दिनों में दुनियाभर में 1,622.72 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। खास बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने लगभग 217 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' के करीब 9 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2025 की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' का सीक्वल है, जो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

'लोगों ने कहा घर तोड़ने वाली', मुश्किल दौर से गुजर रहीं थीं श्रीदेवी; जान्हवी कपूर ने शेयर किया भावुक किस्सा

हाल ही में एक बातचीत के दौरान जान्हवी कपूर ने अपनी मां श्रीदेवी के जीवन के उस मुश्किल दौर को याद किया, जब उन्होंने बोनी कपूर से शादी करने का फैसला लिया था। जाह्नवी ने बताया कि उन्होंने अपनी मां का एक पुराना इंटरव्यू देखा था, जिससे उन्हें समझ आया कि उस समय श्रीदेवी को कितनी ट्रोलिंग और तकलीफों का सामना करना पड़ा था।

वो अंदर ही अंदर परेशान रहती थीं

उन्होंने कहा, 'मैंने वो सफर देखा है। जब मां हमारे साथ थीं, तब लोग उनके लिए बहुत अच्छे नहीं थे। उन्हें 'घर तोड़ने वाली' तक कहा गया और कई तरह की बुरी बातें कही गईं। इसका असर उनके मन पर पड़ा था और वो अंदर ही अंदर इससे परेशान रहती थीं। लेकिन समय के साथ लोग बदल जाते हैं...जब लोग चले जाते हैं, तो लोग उनके बारे अच्छा ह सोचते हैं।' जान्हवी ने आगे कहा, 'अब मैं उन्हें समझ पाती हूं और मुझे अफसोस है कि पहले मैं उन्हें समझ नहीं पाई। बचपन में मैं चीजों को अलग नजर से देखती थी, लेकिन वो उस समय प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और पर्सनल कई चीजों से जूझ रही थीं।'

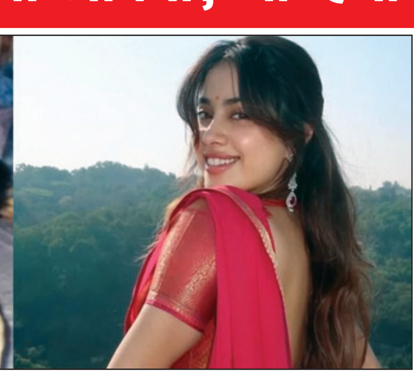

कब हुई थी बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी

बता दें कि बोनी कपूर की पहली शादी मोना शौरी कपूर से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे हैं - अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। इसके बाद बोनी कपूर ने 1996 में श्रीदेवी से शादी की। दोनों की दो बेटियां हैं– जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। शुरूआत में काफी विवादों के बावजूद, दोनों अंत तक साथ रहे। बता दें कि 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में दुबई के एक हॉटल के बाथरूम में डूबने से निधन हो गया था।

जान्हवी कपूर का वर्कफ्रंट

जान्हवी कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें, तो एक्ट्रेस आखिरी बार सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म में नजर आईं थीं। इसमें उनके साथ वरुण धवन, रोहित शरफ और सान्या मल्होत्रा लीड रोल में थे। अब एक्टेस राम चरण की आने वाली फिल्म पेद्दी में नजर आएंगी, जो इसी साल रिलीज होने वाली है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 के थीम टुगैदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस को केंद्र में रखते हुए, पीजीआईएमईआर द्वारा कार्यशाला का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 के थीम टुगैदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस को केंद्र में रखते हुए, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के आहार विज्ञान विभाग ने सरकारी मॉडल हाई स्कूल, सेक्टर 11, चंडीगढ़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को टुगैदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस विषय पर गहन चर्चा, संवादात्मक सत्र और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूक किया गया। कार्यशाला का नेतृत्व करते हुए डॉ. नैन्सी साहनी, चीफ डाइटीशियन एवं विभागाध्यक्ष, आहार विज्ञान विभाग ने किशोरों और स्कूल-बच्चों के लिए स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर विस्तृत जानकारी साझा की। वरिष्ठ डाइटीशियन दीपिका पुरी, सहायक डाइटीशियनों एवं डाइटेटिक्स छात्रों की टीम ने बताया कि स्वास्थ्य के शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी पक्ष महत्वपूर्ण हैं और ये मिलकर बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं।

डॉ. नैन्सी साहनी ने कहा, पोषण प्रतिरक्षा को मजबूत करने, विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा विशेष रूप से किशोरावस्था के बच्चों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने में सक्षम है। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती बिंदु पुरी, जिन्होंने आयोजन में पूर्ण सहयोग दिया, के साथ बातचीत में डॉ. नैन्सी ने इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक शैक्षणिक संस्थानों को स्वास्थ्य संवर्धन को अपनी नियमित शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों को सही पोषण संबंधी ज्ञान—जो वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हो—मिले और वे इंस्टाग्राम रील कल्चर के भ्रम और भ्रामक जानकारी से बच सकें।

पोषण क्विज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक और आनंद के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में कार्यशाला के सभी विद्यार्थियों को फल आधारित नाश्ते भी वितरित किए गए। इस पहल ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर को सार्थक बनाया और पीजीआईएमईआर की पोषण-सेवा दर्शन को पुनः रेखांकित किया—यह याद दिलाते हुए कि स्वास्थ्य की शुरूआत अक्सर भोजन की थाली में किए गए सूझबूझ भरे विकल्पों से होती है और आज के बच्चे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके पथ प्रदर्शक बन सकते हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में एलपीजी उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की

पंचकूला जिले में घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं: उपायुक्त सतपाल शर्मा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर घरेलू एवं कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में सम्बंधित अधिकारीयों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और एलपीजी उपलब्धता और आपूर्ति के संबंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक के उपरांत उपायुक्त ने बताया की जिला में घरेलू गैस एवं कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में जिले में कुल 12 अधिकृत गैस एजेंसियां सुचारु रूप से कार्यरत हैं तथा इनके पास गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है। श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि जिले में पीएनजी कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होने बताया कि गैस आपूर्ति व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।

उन्होने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग सामान्य रूप से जारी है तथा आपूर्ति भी नियमित रूप से की जा रही है। उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार एसएमएस, मोबाइल ऐप अथवा ऑनलाइन माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। गैस की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, घबराहट में (पैनिक) बुकिंग न करें तथा केवल आवश्यकता होने पर ही गैस सिलेंडर बुक करवाएं। साथ ही अनावश्यक रूप से अतिरिक्त गैस सिलेंडर का भंडारण न करें। इसके अतिरिक्त, यदि किसी उपभोक्ता/संस्थान को कमर्शियल गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है, तो संबंधित उपभोक्ता के पास वैध कमर्शियल गैस कनेक्शन अथवा पीएनजी कनेक्शन होना अनिवार्य है। ऐसे उपभोक्ताओं को नियमानुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बिना वैध कनेक्शन के कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त करना नियमों के विरुद्ध है।

उन्होने बताया कि जिन व्यक्तियों (जैसे श्रमिक/प्रवासी मजदूर) के पास कोई पंजीकृत घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है, वे अपनी आवश्यकता अनुसार पंचकूला जिले की किसी भी अधिकृत गैस एजेंसी से 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर सीधे खरीद सकते हैं। उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी कार्य दिवस में दूरभाष नंबर 0172-2929353 पर संपर्क कर अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा ताकि गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रहे। इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला श्री चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका श्री संयम गर्ग , नगराधीश जागृति, डीआरओ डॉ कुलदीप, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्री जतिन मित्तल सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे ।

बेटियों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: नरेन्द्र सिंह

नेचर कैंप थापली में विद्यार्थियों ने मंगलवार की ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूर्ण की

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय नेचर कैंप थापली भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज विद्यार्थियों ने निर्धारित ट्रैकिंग गतिविधि को सफलतापूर्वक किया। ट्रैकिंग के दौरान लड़किया गद गद नजर आई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रकृति के निकट लाकर उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना है।

युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि बेटियों के हितों की रक्षा करना हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है बेटियां इस प्रकार की गतिविधियों में भी भाग ले यह भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। नेचर कैंप थापली में भी बेटियों को आने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है और ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना का विकास करती हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास, खेल एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है।

नरेंद्र सिंह ने बताया कि नेचर कैंप थापली के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और ट्रैकिंग सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझ रहे हैं। रेंज ऑफिसर ने बताया की ट्रैकिंग के दौरान विद्यार्थियों ने प्राकृतिक पगडंडियों पर चलते हुए विभिन्न वनस्पतियों, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने प्रकृति के बीच बिताए समय को प्रेरणादायक बताते हुए इसे एक अविस्मरणीय अनुभव कहा।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने हरियाणा सरकार एवं युवा कल्याण विभाग का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा जताई। थापली इवेंट की मुख्य समन्वयक नैन्सी नैन ने गतिविधियों का सफल संचालन किया, वहीं सहयोगी प्रियंशु सैनी ने भी आयोजन को सुचारु रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मनीमाजरा ईडब्ल्यूएस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी टैक्स के फरमान का किया कड़ा विरोध

सिटी दर्पण संवाददाता
मनीमाजरा

मनीमाजरा ईडब्ल्यूएस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैठक में नगर निगम द्वारा पुनर्वास कॉलोनियों में भेजे जा रहे प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिसों पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम सुंदर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबीर सिंह भारतीय और चेयरमैन सुभाष धीमान ने संयुक्त बयान जारी करते हुए प्रशासन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इंदिरा कॉलोनी और अन्य पुनर्वास बस्तियों में जो मकान चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को दिए गए थे, उनका क्षेत्रफल 25 गज भी पूरा नहीं है। ऐसे छोटे मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स थोपना गरीबों के साथ भद्दा मजाक है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यहाँ के बाशिंदे इस टैक्स का पुरजोर विरोध करते हैं और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजबीर सिंह भारतीय ने कहा कि गरीब आदमी पहले से ही गैस, बिजली, पानी और गार्बेज कलेक्शन की बढ़ी हुई दरों से त्रस्त है। अब प्रॉपर्टी टैक्स का नया बोझ डालकर प्रशासन गरीबों की जेब पर डाका मार रहा है। चंडीगढ़ जैसे शहर में एक आम आदमी का गुजर-बसर करना अब दूभर होता जा रहा है। एसोसिएशन ने शिक्षा के बढ़ते खर्च पर भी चिंता जताई। चेयरमैन सुभाष धीमान और प्रधान श्याम सुंदर सयुंक्त बयान जारी करके बताया कि अप्रैल का महीना बच्चों के दाखिले का समय है। उपाध्यक्ष राजबीर सिंह भारतीय व सैक्टर 26 के प्रसिद्ध समाजसेवी अजय कुमार ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिटी ब्यूटीफुल केवल कंक्रीट की सड़कों और ईंट-पत्थरों से सुंदर नहीं बनता। शहर की असली सुंदरता वहां रहने वाले नागरिकों के चेहरों की मुस्कराहट से होती है। लेकिन आज प्रशासन गरीब विरोधी नीतियां लागू कर उस मुस्कराहट को छीनने का काम कर रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

उपायुक्त ने दयालु-2 योजना के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

पंचकूला। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सांख्यिकीय अधिकारी श्री सुनील कुमार जाखड़ ने जिले में दयालु-2 योजना के तहत प्राप्त मामलों की जानकारी दी। बैठक के दौरान जिले से प्राप्त 17 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें कुत्ते के काटने सहित अन्य मामलों में मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अन्य मामलों के संबंध में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) पंचकूला अपने स्तर पर संबंधित चिकित्सकों के साथ बैठक कर चिकित्सा प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता एवं चोट की गंभीरता की जांच सुनिश्चित करें, ताकि पात्र गरीब एवं पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जा सके। बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा दयालु-2 योजना के तहत दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्तियों के परिजनों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस अवसर पर सचिव आरटीए हैरतजीत कौर, एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त श्रीमती सिमरनजीत कौर, एसीपी श्री सुरेंद्र सिंह, सीएमओ कार्यालय से प्रतिनिधि डॉ. संजीव जैन, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री आशीष चौहान सहित पीएमडीए व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ ने लापता बच्चे जग्गा सिंह को उसके परिवार से फिर से मिलाने में मदद की

चंडीगढ़। समन्वित प्रयासों और आधार-आधारित पहचान के प्रभावी उपयोग के एक उल्लेखनीय उदाहरण में, क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ ने लापता बच्चे जग्गा सिंह को महीनों की जुदाई के बाद उसके परिवार से सफलतापूर्वक फिर से मिलाने में मदद की है। जग्गा सिंह, लगभग 50-60% बौद्धिक अक्षमता वाला बच्चा, 20 अगस्त को स्थानीय मेले के दौरान लापता हो गया था। उसी रात करीब 1:30 बजे, स्थानीय पुलिस ने उसे यमुनानगर के गांव छाछरौली के पास पाया। संवाद करने की उसकी सीमित क्षमता के कारण, बच्चा अपनी पहचान या परिवार के बारे में विवरण साझा करने में असमर्थ था, जिससे ट्रेसिंग प्रक्रिया विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गई। स्थानीय पुलिस के निरंतर प्रयासों के बावजूद, जिसमें बच्चे के वीडियो प्रसारित कर लीड्स इकट्ठा करना शामिल था, परिवार के बारे में कोई तत्काल जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। बच्चे को उसके बाद एक बाल देखभाल संस्थान के संरक्षण में रख दिया गया, जहां उसकी पहचान के लिए प्रयास जारी रखे गए। पहचान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बच्चे के लिए आधार नामांकन शुरू किया गया। हालांकि, नामांकन डुप्लिकेट के रूप में अस्वीकार कर दिया गया, जो पूर्व आधार रिकॉर्ड के अस्तित्व का संकेत था। इस लीड की संभावना को पहचानते हुए, मामला क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को बढ़ा दिया गया। मिस बबीता रानी, असिस्टेंट मैनेजर (हरियाणा) के मार्गदर्शन में और मिस्टर दीपक, बाल देखभाल संस्थान के लीगल एडवाइजर के समर्थन से, उन्नत आधार खोज तंत्रों का उपयोग किया गया। इससे बच्चे का पता और परिवार के संपर्क विवरण सहित महत्वपूर्ण जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त हो गई। सत्यापन और समन्वय के बाद, जग्गा सिंह को 28 मार्च 2026 को उसके माता-पिता से सफलतापूर्वक मिला दिया गया, जिससे परिवार को अपार राहत और खुशी मिली। यह मामला आधार की पहचान सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और दशार्ता है कि कैसे तकनीक, दृढ़ प्रशासनिक और संस्थागत प्रयासों के साथ मिलकर, परिवारों को बहाल करने और कमजोर व्यक्तियों को आशा प्रदान करने में मदद कर सकती है।

जिला की मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है गेंहू की खरीद और उठान का कार्य

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की आवक शुरू होने के साथ खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 1839 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 27 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि हैफेड द्वारा 56 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद पंचकूला अनाज मंडी से, 1050 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद बरवाला अनाज मंडी से और 307 मीट्रिक टन रायपुररानी अनाज मंडी से की गई। इसी प्रकार हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से 208 मीट्रिक टन तथा रायपुररानी अनाज मंडी से से 218 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 27 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा मॉडल जेल, चंडीगढ़ में अपरिपक्व रिहाई विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जेल विजिटिंग वकीलों तथा जेल पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए जेल प्रशासन के समन्वय से आयोजित किया गया। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, प्रतिभागियों को पात्र दोषियों के मामलों को उनकी समय से पूर्व रिहाई के लिए प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने हेतु जागरूक एवं मार्गदर्शित किया गया।

प्रात:कालीन निरीक्षण अभियान से पंचकूला में साफ-सफाई और नागरिक व्यवस्था हुई मजबूत

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

नगर निगम पंचकूला के आयुक्त श्री विनय कुमार के नेतृत्व में चल रहा प्रातःकालीन निरीक्षण अभियान शहर में स्वच्छता व्यवस्था, नागरिक अवसंरचना और जनभागीदारी को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। अभियान के 18वें दिन सेक्टर-12 में निरीक्षण किया गया, जिसमें घर-घर से कचरा संग्रहण, पार्कों का रखरखाव, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, सामुदायिक केंद्रों के प्रबंधन तथा नगर निगम की मशीनरी की सूची (इन्वेंट्री) की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान एक प्रभावी जागरूकता अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें मेशान एवं आसमान फाउंडेशन के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और डांस प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र भी शामिल हुए, जिन्होंने स्वच्छता और कचरे के समुचित निपटान का संदेश दिया।

अभियान के 19वें दिन सेक्टर 12अ एवं 14 में निरीक्षण किया गया, जिसमें स्वच्छता की स्थिति, घर-घर से कचरा संग्रहण, सड़कों की मरम्मत तथा अस्थायी अतिक्रमणों की समीक्षा की गई। सेक्टर-14 के बाजार स्थित गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट एवं किसान मंडी में बेहतर स्वच्छता और व्यवस्थापन की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, सार्थक मॉडल संस्कृति स्कूल में एक सामाजिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ विद्यार्थियों को स्वच्छता और स्वास्थ्यकर जीवनशैली के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

आयुक्त ने पुनः दोहराया कि इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य निरंतर निगरानी, समयबद्ध कार्रवाई तथा नागरिकों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे पंचकूला में स्वच्छता और समग्र नागरिक प्रबंधन में निरंतर सुधार हो सके। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम एक स्वच्छ, हरित एवं नागरिक-केन्द्रित पंचकूला के निर्माण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

सीसीए पंजाब ने भारतनेट कार्यक्रम के तहत क्वालिटी एफटीटीएच कनेक्टिविटी के लिए फील्ड चेक किए

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत, नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, पंजाब, डिजिटल भारत निधि से वित्त पोषित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत प्रदान की जा रही एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) कनेक्शनों की भौतिक सत्यापन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में फील्ड विजिट्स कर रहा है। यह सत्यापन अभियान सेवा वितरण की स्थिति का आकलन करने व कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं सुनिश्चित करने के लक्ष्य से संचालित है। विजिट्स के दौरान सीसीए टीमें सब्सक्राइबर्स व स्थानीय हितधारकों से बातचीत कर सेवाओं की गुणवत्ता, पहुंच व प्रभावशीलता पर इनपुट ले रही हैं। उपभोक्ताओं से प्राप्त इनपुट बताते हैं कि एफटीटीएच कनेक्टिविटी ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स व संचार सुविधाओं तक पहुंच सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार ला रही है। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की सभी के लिए इंटरनेट सुनिश्चित करने व डिजिटल डिवाइड को पाटने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दृष्टि से मेल खाती है। प्रयास हर घर में इंटरनेट पहुंच प्रदान करने व समावेशी डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से भी जुड़े हैं। फील्ड सत्यापन अभियान सीसीए पंजाब के निरंतर निगरानी तंत्र का हिस्सा है जो डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन व अंतिम छोर तक सहज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। सीसीए पंजाब ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने व सरकारी कार्यक्रमों के लाभ राज्य के हर कोने तक पहुंचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

समारोह | **वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य व कानूनी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक**

डीएलएसए पंचकूला द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

श्री अजय कुमार घनघस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला ने बताया कि श्री जगदीप सिंह लोहान, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हलसा) के निदेर्शों के अनुपालन में, और श्री संजय संधिर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के कुशल मार्गदर्शन में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीनियर सिटिजन्स क्लब, सेक्टर-25, पंचकूला में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के बीच स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, कानूनी अधिकारों और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। यह पहल समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचने और यह सुनिश्चित करने के लिए डीएलएसए पंचकूला के निरंतर प्रयासों को दशार्ती है कि वे सूचित, सशक्त और समर्थित हों।

इस अवसर पर, श्री मनबीर राठी, पैनल अधिवक्ता, और श्री वी.एन. शुक्ला, पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी), ने संसाधन व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन्स) के रूप में कार्य किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों की सुरक्षा में विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका के बारे में जागरूक किया। उन्होंने समय पर चिकित्सा देखभाल, निवारक स्वास्थ्य जांच और समग्र भलाई बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। श्री अजय कुमार घनघस ने सभा को संबोधित किया और विश्व स्वास्थ्य दिवस के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। उन्होंने उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और कानूनी या सामाजिक मुद्दों से संबंधित किसी भी सहायता के लिए डीएलएसए पंचकूला से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस कार्यक्रम में सीनियर सिटिजन्स क्लब के सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्होंने डीएलएसए पंचकूला द्वारा की गई इस पहल की सराहना की। उन्होंने ऐसे जानकारीपूर्ण और संवादात्मक सत्र के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसने न केवल उनकी चिंताओं का समाधान किया, बल्कि मूल्यवान मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम का समापन एक संदेश के साथ हुआ, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सामूहिक ज़िम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया गया। डीएलएसए पंचकूला ने भविष्य में भी इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।